[श्री वेणी शंकर शर्मा]

नहीं कर सकता । इसलिए मैंने संशोधन में यह कहा है कि मेम्बर्स आफ दि पार्लियामेंट को भी इस बिल के दायरे में लाना चाहिए ।

प्राइम मिनिस्टर के सम्बन्ध में कम्पीटेंट अथारिटी का जो प्रश्न है उस के लिए मेरा सुझाव है कि प्रेसीडेंट आफ इंडिया ही कांपीटेंट अथारिटी बनाना चाहिए । अभी-अभी गृह मंत्री जी ने कहा है कि प्रेसीडेंट आफ इंडिया तो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ही काम करता है । यह कोई अर्थ नहीं रखता । मुझे एक छोटी सी कहावत याद आती है कि कोई आदमी किसी से उसकी गाड़ी मांगने गया तो उस ने कहा कि गाड़ी में तो कट्टा बंधा हुआ है, कैसे दूं । उसने कहा कट्टा खोल ले । गृह मंत्री का कथन भी कुछ ऐसा ही है । अगर संविधान में कुछ ऐसी बातें हैं जो इस में बाधक हैं, तो हम उस का संशोधन कर सकते हैं और हम प्रेसीडेंट को यह अधिकार देते हुए प्राइम मिनिस्टर की सलाह से मुक्त कर सकते हैं ।

अतएव मेरा कहना है कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट के मेम्बरों को छोड़ देते हैं तो उसका असर यह होगा कि स्टेट्स में भी चीफ मिनिस्टर्स और जितने एम० एल० एज० और एम० एल० सीज० हैं वह भी छोड़ दिए जायेंगे । इतने राजनैतिक पुरुष इस बिल के दायरे से छूट जाते हैं तो जो करप्शन, फेवरिटिज्म और निपोटिज्म का वातावरण है उस में कहां तक न्याय हो सकता है यह मेरी समझ में नहीं आता ।

इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि न्याय के हित में, देश के हित में और लोक हित में यह संशोधन कि हम प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर्स को और पार्लियामेंट के मेम्बर्स तथा असेम्बली और कौंसिल के सदस्यों को भी इस में शामिल करें, स्वीकार कर लें । एक बात और मैं कहना चाहता हूं, यह कहा जाता है कि स्टेट्स अपने अलग कानून बनाएंगे लेकिन जब हम अपना कानून बनाएंगे तो स्टेट्स के कानून में उसी का एक प्रतिविम्ब होगा । इसलिए हमें यह जो कानून बनाना है वह बिलकुल निष्पक्ष बनाना है ।

15.04 hrs.

MOTION RE : AGITATION FOR SEPARATE TELENGANA STATE

MR. SPEAKER : We shall now take up the Motion standing in the name of Shri K. L. Gupta, regarding Telengana. Already we have allotted 2-1/2 hours for this discussion. Some members have approached me to say that the time allotted is not enough. There might be a little extension of time, but not more than half an hour or so. I hope the House will try to conclude the discussion with that time.

श्रीमती लक्ष्मी बाई (मेडक): तीन घंटे इस के लिए बहुत कम हैं । 8 बजे से पहले यह खत्म नहीं हो सकता । हम लोगों को कभी टाइम नहीं मिलता ....

अध्यक्ष महोदय : इस दफा आप को जरूर मिलेगा ।

SHRI GANGA REDDY (Adilabad): The time is not sufficient.

SHRI M. N. REDDY (Nizamabad) : We have already written to you.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : I beg to move:

> "That this House takes serious note of the agitation for a separate State of Telengana and urges upon the Government to take necessary steps."

अध्यक्ष महोदय, तेलंगाना के अन्दर पिछले सात महीने से जोरदार आन्दोलन चल रहा है और आठवां महीना शुरू हो गया, वहां पर स्कूल और कालेज बन्द हैं । करीब-करीब एक साल विद्यार्थियों का खत्म हो गया । बगैर शिक्षा लिए । वहां पर कई महीने तक सरकारी दफ्तर भी बन्द रहे और ऐसा मालूम होता है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन पैरालाइज होता जा रहा है लेकिन जैसा कि अंग्रेज सरकार

करती थी कि पहले वह कोई समस्या होती थी तो उस की तरफ से इनडिफरेंट रहती थी, उस की ओर ध्यान नहीं देती थी और उस के बाद उस को बुरा भला कहती थी । बाद में उस को रेप्रेशन के जरिए से, डंडे के जरिए से दबाती थी । इस सरकार ने भी इसी तरह से तेलंगाना वालों के साथ वर्ताव किया । पहले जो उन की समस्याएं थीं उन के साथ बेरुखी का वर्ताव किया, इनडिफरेंस शो किया फिर उन को रिब्यूक किया और उस के बाद डंडे के जरिए से, पुलिस के जरिए से उन को दबाने की कोशिश की जा रही है । लेकिन प्रजातंत्र के अन्दर यह उस का सही रास्ता नहीं है । कई बार यह सवाल कांग्रेस पार्टी के सामने आया, उन्होंने उसे को हल करने की भी कोशिश की । मैं इस के इतिहास में नहीं जाता । आप मेरे से इत्तफाक करेंगे और शायद चव्हाण साहब भी इस बात पर सहमत होंगे कि तेलंगाना के लोगों के ऊपर ज्यादती हुई है । इस में कोई दो राय नहीं है । वहां पर शिक्षा में, खेती की सहायता में, इरीगेशन फैसिलिटीज़ में, बिजली देने में, नये कालेज खोलने में यानी जितने भी डेवलपमेंट के साधन हैं 22 साल में तेलंगाना की ओर जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया गया । इस के साथ-साथ सरकारी नौकरियों में भी बड़े-बड़े अफसरों के अन्दर भी उन का जो अनुपात होना चाहिए था वह अनुपात नहीं दिया गया । मैं चाहूंगा कि स्वयं गृह मंत्री महोदय इस बात को कहें और इस बात को मानें कि तेलंगाना वालों के साथ 22 साल में कितनी ज्यादती हुई है। पिछले 13-14 साल से तेलंगाना के लोगों के साथ डेवलपमेंट के प्रोग्राम में चाहे वह खेती का हो, इरीगेशन का हो, बिजली पानी का का हो या शिक्षा का हो, जिस तरह का व्यवहार होना चाहिए था, वह नहीं हुआ । ठीक तरह से डेवलपमेंट उस का नहीं हुआ । इस के अतिरिक्त नौकरियों के अन्दर भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इस में भी कोई दो राये नहीं हैं और मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस के बारे में कुछ कहें ।

दूसरे, मैं एक केस आंध्र हाई कोर्ट का सदन के सामने रखना चाहता हूं जिस में हाई कोर्ट के जजेज़ ने आन्ध्र के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स दिए हैं और जिस में यह कहा है कि सरकार ने तेलंगाना के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है । यह बात बिलकुल ठीक है । मैं वह आप के सामने पढ़ना चाहता हूं :

"There is every justification for the first petitioner and other petitioners to complain that this action is *mala fide* and is based on regional bias".

This is a very damaging and serious statement and I think the Government of India will take note of it. I am sorry that the Minister has so far taken no action on it.

SHRI M. N. REDDY : I request that the copy of the judgment referred to by the hon. Member may be laid on the Table of the House.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I am prepared to lay it on the Table of the House.

"While there may be justification for alleging regional bias in the matter of promotion, it is, however, difficult to hold on the basis of these few instances alone that the Chief Minister...."

But still, on the facts now established, the judge says:

"I am constrained to hold that so far as the allegation that discriminatory treatment was meted out to the petitioners and undue preference was shown to respondent No. 6 by the Minister concerned and the Chief Minister on account of irrelevant consideration is concerned, is fully established."

अध्यक्ष महोदय, इस के अन्दर मुख्य मंत्री और मंत्री महोदय दोनों कुसूरवार हैं ।

"The promotion of No. 6 in preference to other officers mentioned in the note of the Secretary in paragraph 48 of the note file is contrary to the rules. In view

[Shri Kanwar Lal Gupta]

of the very serious adverse remarks against this officer, it is really surprising how the Minister and the Chief Minister found him most suitable for promotion to the cadre of Superintending Engineer. It only shows that (they point out that the particular Executive Engineer does not possess ME qualification) if they thought of promoting a particular person nothing stands in the way: neither the fact that he is not even a graduate engineer, nor the fact that he is a person whose technical proficiency is inadequate, nor even the further fact that his integrity is doubtful. Such a promotion cannot be held valid in law; it cannot by any canons of administration be justified."

यह बहुत लम्बा है, इस लिये मैं इसे ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता हूं। लेकिन मेरा कहना यह है कि हाई कोर्ट की स्ट्रिक्चर्स है, जिसमें वहां के मुख्य मंत्री को दोषी ठहराया गया है कि वे एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र में भेद-भाव करते हैं—नौकरियों में और सब चीजों में।

अध्यक्ष महोदय, यह जो डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग है, उन के अन्दर जो सस्पीशन है, वह जैनुइन है। जब तक उन का सस्पीशन दूर नहीं किया जाता, उन के अन्दर क्राइसेज आफ़ कान्फीडेन्स रहेगा, आप चाहे डण्डे के ज़ोर से उन पर विश्वास लादने की कोशिश करें, इस में कामयाब नहीं हो सकते। जब तक उन के दिलों को नहीं जीता जायगा, तब तक कोई काम होने वाला नहीं है। आपको याद है—जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेन्ट दिया था कि मुल्की और गैर मुल्की में भेद-भाव नहीं हो सकता और जब उन की सर्विसिज के अन्दर कोई गारन्टी नहीं रही, तो यह आग और शुब्हा और ज्यादा फैल गया। जो पहले जैन्टिलमैन-एग्रीमेंट था, उस पर भी अमल नहीं हुआ। जो कमेटी बनाई गई, उस में भी ठीक काम नहीं हुआ। मैं यह ज़रूर कहूंगा कि इस में कुछ मात्रा में तेलंगाना के डीलर्स भी दोषी थे। उन को उस समय जितने ज़ोर से आवाज उठानी चाहिए थी, वह नहीं उठाई·····

श्री एम० नारायण रेड्डी : वे सब कांग्रेसी लीडर्स थे।

श्री कंवर लाल गुप्त : जब जनता ने देख लिया कि उन के साथ भेद-भाव हो रहा है, उन्होंने बगावत का झण्डा खड़ा किया। उन्होंने प्रधान मंत्री को पत्र भेजा, उसी समय सुप्रीम कोर्ट के जजमेन्ट के साथ एक और जजमेन्ट आया, जिसमें डा० चेन्ना रेड्डी साहब को मेम्बरी से बरखास्त किया। उस के बाद—जैसा, अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कई बार कहा है, जैसे, के० डी० मालवीय को क्यों चेयरमैन बनाया, लेकिन अब मैं महसूस करता हूं, कि कांग्रेस के ये जो फ्रस्ट्रेटेड मिनिस्टर्ज होते हैं, अगर इन को कुछ न कुछ बनाया जाय, चाहे एम्बेसेडर बनाइये, चाहे चेयरमैन बनाइये, कुछ-न-कुछ प्रावीजन इन के लिये ज़रूर करना चाहिए, अगर नहीं किया गया तो ये लोग बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। यही चेन्ना रेड्डी साहब जब तक मंत्री, थे, कभी नहीं बोले, लेकिन जैसे ही मंत्री पद से हटे, ये जाकर उन में शामिल हो गये, उन के नेता बन गये और एक तरह से हा-हाकार मचा दिया। यह केवल चेन्ना रेड्डी की ही बात नहीं है, आप देखिये—कृष्णा मेनन जब हटे और जब यहां मेम्बर बने, उन्होंने प्रधान मंत्री को ही बहकाना शुरू कर दिया और आज यह हालत है हो गई है कि देश की सिक्योरिटी ही खतरे में आ गई है। ····· (**व्यवधान**) ····स्वयं प्रधान मंत्री को जब यह महसूस हुआ कि मेरी कुर्सी जा रही है, तो उन्होंने सी० बी० गुप्ता को कहा और आज हालत क्या हो गई है—कांग्रेस के दो टुकड़े होने जा रहे हैं।

इस लिये मेरा कहना यह है कि कांग्रेस के लीडर्स जो फ्रस्ट्रेटेड हो जायें या कुर्सी छूट जाये, देश के इन्टरेस्ट में है कि पार्लियामेन्ट उन के लिये एक फण्ड बना दे ताकि वे उत्पात न करें। पचास करोड़ रुपये का नुकसान इस तेलंगाना के एजीटेशन से हो चुका है। चेन्ना रेड्डी अगर मंत्री बने रहते या किसी

दूसरे प्रोफैशन में डाल दिये जाते तो इतना झगड़ा न होता । इस लिये जरूरी है कि इन कांग्रेस के नेताओं के लिये, जो रिजैक्टेड हो जायं, उन के लिये पार्लियामेंन्ट प्रबन्ध करे और मेरा वोट इस काम में उन के समर्थन में होगा ···

श्री पीलू मोदी (गोधरा): एक गऊ-शाला शुरू करनी चाहिये ।

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, इस का मुख्य कारण क्या है ? इस का मुख्य कारण यह है कि हमारे देश में इकानामिक रिजनल इम्बैलेंसेज है । हमारे यहां जो भी डेवलपमेंट हुआ—एक जगह पर ज्यादा कन्सेंट्रेट हुआ, कुछ हिस्से को ज्यादा लाभ हुआ और बाकी का हिस्सा पिछड़ा रह गया । गरीब गरीब होता गया और अमीर अमीर होता गया । यही बात आन्ध्र में हुई—तेलंगाना का हिस्सा डवैलप होने से रह गया और आन्ध्र पर ज्यादा खर्च हुआ, परिणाम यह हुआ कि तेलंगाना के गरीब और ज्यादा गरीब हो गये और आन्ध्र के लोग और ज्यादा अमीर हो गये । कन्सेन्ट्रेशन एक सैक्टर में ज्यादा हुआ और दूसरी जगह पर नहीं हुआ, हालांकि हम ने दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, वांचू कमेटी और पांडे कमेटी बैठाई, उन्होंने भी रिकमेंडेशन दी कि रिजनल इम्बैलेंसेज हटना चाहिये, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया । अगर ये रिजनल इम्बैलेंसेज खत्म नहीं होंगे तो एक तेलंगाना नहीं, 100 तेलंगाना इस देश में हो जायेंगे। विदर्भ भी बनेगा, सौराष्ट्र भी बनेगा, इसलिये जिन-जिन प्रदेशों में इकानामाकि इम्बैलेंसेज हैं, सरकार को वहां सब से ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिये, ताकि उन का ज्यादा-से-ज्यादा डवेलपमेन्ट हो सके ।

अब इसका आल्टरनेटिव क्या है ? क्या इस आन्दोलन को समाप्त करने के लिये केवल वायदा करने से काम चल जायगा ? लेकिन आपने वायदा कर लिया, प्रधान मंत्री ने वायदा किया, स्टेटमेन्ट दिया, नतीजा कुछ नहीं निकला । इस के लिये कोई न कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, ताकि तेलंगाना के लोगों के अन्दर विश्वास पैदा हो, देश तुम्हारी दिक्कत को समझता है, तुम्हारे दुख को समझ कर उस को दूर करने की कोशिश करेगा । इस लिये मैं सरकार से कहूंगा कि कोई इफैक्टिव कदम उठाये ताकि क्राइसेज आफ़ कान्फिडेन्स खत्म हो । केवल एक आदमी के आश्वासन दे देने से वह खत्म नहीं होगा, ऐसी प्राबलम्ज को नैशनल लेवल पर हल करने की आदत डालनी चाहिये, इस में अपोजीशन को भी बैलैंसिग रोल अदा करना चाहिये । नेशनल लेवल पर हल करना चाहिये । सब पार्टीज के लीडर्स उन को बुला कर विश्वास दिलायें कि हम मानते हैं कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ न्याय करवायेंगे । इस प्रकार का नेशनल प्लानिंग, नेशनल कौंशंसेस क्रियेट कर के तेलंगाना के लोगों के अन्दर जो क्राइसेज आफ़ कान्फिडेन्स है, उस को दूर करने की कोशिश करनी चाहिये । सरकार केवल अपनी पार्टी के जरिये या केवल एक पार्टी के जरिये इस को हल करने की कोशिश करेगी तो यह समस्या हल होने वाली नहीं है ।

मैं समझता हूं कि शायद मेरी बात से मेरे कुछ मित्र राजी हों या न हों, लेकिन मैं यह अच्छा नहीं समझता कि आन्ध्र का बटवारा हो, यह राष्ट्र के हित में नहीं होगा । अगर एक जगह बटवारा हुआ तो एक पलड-गेट खुल जायेगा, देश के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे । यह ठीक है कि अभी तक इस सरकार की यह परम्परा रही है कि जहां-जहां वायलेंस हुआ, आग लगी, स्ट्राइक हुई, वहां सरकार ने बात मान ली—चाहे नागालैंड हो या आसाम में जो एक अलग सूबा बनाया गया, या महाराष्ट्र हो, अब तक यह सरकार वायलेंस के आगे हमेशा

(श्री कंवर लाल गुप्त)

झुकती रही है । आप कहेंगे कि तेलंगाना के मामले में नहीं झुकी--इस के कुछ पोलिटीकल रीजन्स थे । प्रधान मंत्री चीफ मिनिस्टर को अपनी तरफ़ खींचना चाहती थीं और दूसरे अपनी तरफ खींचना चाहते थे, नतीजा यह हुआ कि वहां के मुख्य मंत्री दोनों ग्रुपों को खश करने की कोशिश में रहे, इस लिये बटवारा नहीं हुआ । ऐसी बात नहीं है कि आप में कुछ गट्स आ गई, या समझ आ गई । आज वहां पर जो आन्दोलन चल रहा है, वह अभी भी उसी तरह से चल रहा है, लेकिन पहले से कुछ स्थिति ठीक है । आप कुछ कदम उठायें । साइकोलाजिकल ट्रीटमेन्ट के लिए पहला कदम यह जरूरी है कि श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी इस्तीफा दें और तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बनाया जाये, जितने लीडर्स हैं उनको रिहा किया जाय और सारे अपोजीशन के साथ मिलकर आप उन लीडर्स को विश्वास दिलायें कि जो आपकी ग्रीवान्सेज है उनको दूर किया जायेगा । तेलंगाना का पीसमील सोल्यूशन करने से भी काम नहीं चलेगा क्योंकि रीजनल इम्बैलेंसेज बहुत सारे प्रान्तों में है । आज यहां तेलंगाना है तो कल दूसरी जगह तेलंगाना न बने, इसका परमानेन्ट हल निकालने के लिये एक हाई पावर्ड कमीशन बनाना पड़ेगा । स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन जो बना था उसने एकोनामिक वायबिलिटी को ध्यान में तो रखा लेकिन उसका ज्यादा जोर लैंग्वेज पर ही रहा---एकोनामिक रीजनल इम्बैलेंसेज की तरफ जितना उसका ध्यान जाना चाहिए था वह नहीं दिया गया । तो मेरा कहना यह है कि वह कमीशन एकोनामिक रीजनल इम्बैलेंसेज को ध्यान में रखे और इसके लिए अगर कहीं पर बाउन्ड्री रीएडजस्टमेन्ट्स भी करने पड़ें तो वह भी करना चाहिए । सरकार जम्मू कश्मीर के बारे में कहती रही कि रीजनल इम्बैलेंसेज नहीं है लेकिन गजेन्द्रगदकर कमीशन ने आंखें खोल दी कि जम्मू के साथ और लद्दाख के साथ दुर्व्यवहार हुआ है--आप उस दिन जवाब नहीं दे सके कि लद्दाख में कितना पैसा खर्च हुआ । जो भी खर्चा हुआ वह नौकरियों में हुआ, डैवलेपमेन्ट पर नहीं और उससे लद्दाख के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ । वहां के लिए कोई बोर्ड नहीं बनाया गया । इसलिए मेरा कहना है कि जो कमीशन बने वह सारे देश की रीजनल इम्बैलेंसेज को देखें और दिक्तों को दूर करने के लिए सजैशन्स दे ।

एक चीज और कहनी है । अभी तक सरकार पिक ऐन्ड चूज की पालिसी अख्तियार करती आई है--किसी कमीशन की रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस जहां उनको सूट की तो मान लिया और जहां पर सूट नहीं की, वहां नहीं माना, यह ठीक नहीं है । एक परम्परा डालनी चाहिए कि जो जुडिशियल कमीशन हो, उसकी रिकमेंडेशन्स को मान लेना चाहिए । अगर आप पिक ऐन्ड चूज करेंगे तो उसके घातक परिणाम हो सकते हैं । इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वहां के नेताओं को छोड़ें, श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी से कहें कि वह इस्तीफा दें और वहां के लोगों को कोई ऐसी गारन्टी दें, सभी मिल करके, कि उनमें विश्वास आये और बैठ करके उनसे प्रार्थना की जाय कि वे एजिटेशन को वापिस लें । लेकिन उससे पहले ये सब कुछ होना चाहिए यानी श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी को इस्तीफा देना चाहिए, लीडर्स को अनकन्डीशनल रिलीज करना चाहिए और नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट सारी अपोजीशन पार्टीज के साथ उनको विश्वास दिलाये । उसके बाद एक कमीशन सारे देश के रीजनल इम्बैलेंसेज के बारे में देखे ।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से कहूंगा कि वह ठोस कदम उठाकर के तेलंगाना में एक तरह से जो अविश्वास पैदा हो रहा है, जो आतंक पैदा हो रहा है, जो आन्दोलन हो रहा है उसको शांत करने के लिए पूरी कोशिश करे ।

MR. SPEAKER : Motion moved:

"That this House takes serious note of the agitation for a separate State of

Telengana and urges upon the Government to take necessary steps. "

There are some amendments.

SHRI PRAKASH VIR SHASTRI (Hapur) : I move :

That in the motion, —

for "takes serious note of the agitation for separate State of Telengana and urges upon the Government to take necessary steps."

substitute—"expresses dissatisfaction over the neglect of entire area of the Telengana region of Andhra Pradesh and urges upon the Government to examine the possibility of a separate Telengana State and take steps towards arriving at a favourable decision soon." (1)

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : I move:

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"It further calls upon : —

(*a*) the leaders and followers of Telengana agitation to eschew all forms of violence ;

(b) the Government of Andhra Pradesh to stop repressions;

(*c*) the Central Government to expedite the eight point programme and also take steps to give statutory powers to the Telengana Regional Committee in the fields assigned to them." (3)

SHRI YASHWANT SINGH KUSHWAH (Bhind) : I move:

That in the motion,—

for "to take necessary steps"

substitute—"either to take steps to abolish linguistic States in the entire country or to accept the demand for the formation for a separate State of Telengana without delay" (4)

SHRI RANGA (Srikakulam) : Mr. Speaker, Sir, this Telengana question has assumed national proportions. For the past eight months it has become a burning issue. Unfortunately, the Government of India as well as the State Government have taken all this time not to find any solution but only to play with it and vainly to sleep over it. They have not been able to sleep over it because the people would not allow them to sleep over it. Recently they have offered some kind of a semi-political solution from the platform of their Congress Party, by directly or indirectly assuring those people that the present Chief Minister, Mr. Brahmananda Reddy would be enabled—I would not like to put it as my hon. friend Mr. Kanwar Lal Gupta has put that he would be removed or he would be dismissed to withdraw from the Chief Ministership in an honourable and decent manner provided, of course, the people would help him by creating peaceful atmosphere. But anyhow it has been taken for granted by the people at large in Andhra as well as in Telengana that Mr. Brahmananda Reddy was expected to leave the very much coveted position of Chief Ministership and make way for the representative of the Telengana to become the Chief Minister. Unfortunately, what has happened is that Mr. Brahmananda Reddy is still adorning the position of the Chief Ministership and the people are left wondering whether he really means what he has said that he would like to leave the place and make way for a Telengani. When he had an opportunity of doing something, what he did was to replace the earlier Ministry of 16 people by the enlarged Ministry of 29 people with an additional promise of taking some more, that way dangling the red carrot before quite a large number of claimants. Beyond that, he has not achieved anything else.

15.25 **hrs.**

[SHRI VASUDEVAN NAIR *in the chair*]

Now, in the very beginning of this agitation, he got together a conference of Opposition leaders and then stated that more than 2,000 people were unduly brought from Andhra and employed stealthily in Telengana and that those 2,000 people were going to be sent away. Very soon, legitimate protests were raised against that statement because they did not go there stealthily. First of all, they were not employed stealthily, they were employed openly on the

[Shri Ranga]

the request or on the needs of Telengana area itself and Telengana people. Most of them happened to be teachers. They had already been employed in Andhra and they were transferred to Telengana area. They were not given any additional salary. Therefore, they had to undergo a lot of trouble in order to put up with this sort of transfer. Any how, they were served notice that they can go back. Naturally, they were annoyed and unhappy, not with Telengana people, but with the administration which had put them to unnecessary trouble. So, some of them had gone to the Supreme Court. And we know the result.

Thereafter, even simultaneously as this was happening, Telengana people, quite a large number of them, took law into their own hands because they found that through lawful means they could not get justice as they conceived that justice to be for themselves. After a time, their demands began to achieve higher and higher tempo and within two months they began to ask for separation and a separate State for themselves.

What was the response given by my hon. friend, the Home Minister here? He was asked to go down there. He would not go; the then Deputy Prime Minister would not go; the Prime Minister would not go. Then, the movement took a violent turn. More and more people came to be killed; more and more properties were destroyed. Thousands and thousands of people who hailed from Andhra were treated very shabbily, very cruelly, in an unjust way, in a very dishonourable manner and in an uncivilised manner also. It was then that the Prime Minister thought of making a flying visit. She made a flying visit almost at midnight and invited all those people to meet her in politically-romantic circumstances. It yielded no reuslt. Then, in order to buttress here efforts, the hon. Home Minister went there.....

SHRI PILOO MODY : At what time;

SHRI RANGA : .....and invited everybody in the same usual fashion but not under similar romantic circumstances. And he left hopes behind, as he generally does wherever he goes. He is an expert in that. Unfortunately, those hopes have not been realised at all.

The people came to be frustrated and the movement reached a higher and higher tempo. It is no good blaming Dr. Chenna Reddy or the other people. Suppose we were in that position; we would certainly have considered it our sacred duty to place ourselves at the head of an agitation like that. And what sort of agitation ? It was not an artificial agitation. The moment it raised its head, I was able to espy, as it would have been possible for any genuine political worker or organizer to espy, that it was a genuine thing. The people were simmering; the people were thinking of a separate Telengana, but they did not have the opportunity of fighting for it. So, it suddenly burst out. The moment it burst out, I could see that there was the genuine feeling of the people. That feeling was not one day's wonder; it has been growing over years. Even in those days when Andhra Pradesh came into existence as a result of the States Reorganization Commission's recommendations, the Telengana people wanted to have their own State, their own separate entity. They made very powerful representations. I supported them; I strengthened them; I told the then Prime Minister and the other people also, 'For God's sake, let them have their own Telengana State at least for ten years as was suggested by the States Reorganization Commission; if thereafter they were not willing, let them go on for for another ten years; and thereafter if they would be willing to go into the bigger entity of Andhra Pradesh, they would be welcome to do so." But they would not heed my advice nor would they heed their demand.

Naturally those people had been thinking on those lines; they were hoping against hope that adequate justice would be done to them. They were given guarantees also. The House has already discussed these guarantees and all that had happened thereafter, on two previous occasions and, therefore, I need not go into all those details now. But I must say one thing. A duty was cast on the Home Minister here to see whether those directives were being carried out or not; no Home Minister had

ever paid any attention to it. If there was any difference of opinion between the local telengana Advisory Committee and the local Ministry, the Governor was expected to intervene and when his advice was not accepted by the then Ministry, to report to the President and see that the aid of the Government of India was invoked. But nothing was done in those directions. And yet, those people were maintaining their patience. Why ? For three or four or five reasons. First of all, there was power in in the Ministries both for the Telengana MLAs and Telengana Ministers, as well as the others; therefore, they did not want to displease the Chief Minister Secondly, on the Telengana Advisory Committee, all the Telengana MLAs were there; the Ministers were also there; somehow or other there was certain amount of log-rolling and they were also silenced from time to time although they were getting dissatisfield. Thirdly, their proceedings could not be made public; therefore, whatever discontent was there could not come in to the open; so, the general public did not have all the details, did not have the facts. That was the reasons why the discontent was simmering and remaining underground The moment somebody gave a pinprick. it burst out. Now we know what is happening.

Is it not high time for the Government here—I need not address myself to the Home Minister alone because today the Government as a whole has got to be tackled; otherwise any one Minister does not seem to be capable of moving the whole cumbersome administrative machinery as well as the Cabinet machinery of this Congress Government under the present circumstances; therefore, let me address myself to this Government as a whole— to realise that it is a genuine demand, that it is a popular demand, that the people are behind it? If only these Telengana MPs here were to have the courage to resign their position here, go back and stand merely in the name of Congress, I am sure most of them would be defeated....

SHRI M. N. REDDY : All of them.

SHRI RANGA : If, on the other hand, they were to resign and go back and stand there in the name of Telengana, I am sure almost all of them would be elected. Such is the feeling. I have very good reason to see say this because I have learnt from so many of my friends who are living there in Telengana as well as Andhras who have given me this information as to how things are going on. What did happen the other day? Unfortunately, this movement has taken a violent turn and that has weakened the hands of so many of us who are the friends of this movement and much more so who are the friends of Telengana people. By the time Dr. Chenna Reddy was arrested, the violent side has more or less subsided to a very great extent. When Dr. Channa Reddy was arrested, when Mr. Konda Laxman was arrested, as luck would have it, there were no violent demonstrations. There were only peaceful demonstrations. But those peaceful demonstrations were absolutely unique, Sir, in the political history of these two cities, Hyderabad and Secunderabad. Tens of thousands of people under a political banner came into the streets and demonstrated their protest against the Government and their support for Telangana movement. To say that these bundhs are artificial and they are all taking place because of violence and so on is not correct. Even without violence they are taking place. These are the things which have led us to feel strongly that the Telengana movement is a popular movement and, therefore, Government ought to give its response. Now how should they give their response?

They have appointed some Committees. They have taken such a long time to publish the reports of those Committees. Why should they have taken all this time ? They might go on saying in the usual way "So many things have got to be studied." They have got to study these things with this crisis in their mind in an emergent manner. They should have been able to produce these reports even if they be tentative reports, saying later on something more in addition to what these people could have said in their draft or tentative reports. Nothing has been achieved till now in that direction.

Secondly, it is high time now for the Government to assure those people that the

[Shri Ranga]

Government of India would keep an open mind in regard to Telengana, separate Telengana and that they would take the earliest possible opportunity as soon as peaceful conditions come to prevail not only in the cities but also in the whole of the countryside of Telengana, that they would ascertain the public opinion there and if public opinion were to favour overwhelmingly a separate Telengana, they would certainly not hesitate to organize a separate Telengana as a kind of a State or sub-State as is happening in Assam and in that way give some satisfaction, temporary satisfaction to the people. In the meanwhile they would implement all these recommendations that would be made by these Committees as well as the other recommendations of the State Committee.

Thirdly, they should no longer cause any more delay in regard to Chief Ministership and they should not leave the choice of the Chief Ministership also entirely to outgoing Chief Minister but to the Telengana MLAs and MPs all put together almost the whole lot of them are Congressmen, possibly may be now of only one section if we are to judge from what has happened day before yesterday in the latest election—let them all sit together, let them reach an agreement upon somebody whom they would like to have as Chief Minister and let that Chief Minister provide a good enough and impartial, just and strong administration and leadership not only for Telengana but also for the Andhras and in that way pave the way for 1972 and in 1972 if the Telengana people do really wish to have a separate Telengana and indicate their decision by electing 75 or 80% of their members in support of that demand, then the Government should be willing to take immediate steps to form a separate State or sub-State for the Telengana people.

One final word of advice to the Telengana people to the extent it can possibly reach them either through the daily papers or through the radio if at all this Government would be willing to send any of our advice through their radio. It is high time for them to realise the mistake that they have made in raising such an awful, unjust, one-sided and unwise campaign against Andhras and the manner in which they have treated those people who were good enough, who were Andhra-minded enough to come and settle down there in the various parts of Telengana. They should learn to treat Andhras as they have been treating non-Andhras who have settled down in Telengana. They should learn to treat each other from whichever area they might be hailing as Indian citizens who deserve to be treated in terms of our constitution as equal citizens. I hope God would give a bit of his wisdom to this Government here to do the right thing by the people of Telengana as well as Andhra and also the whole of India.

DR. MELKOTE (Hyderabad) : Mr. Chairman, Sir, I must say that if anybody visits Telengana now he will be met with either one or two slogans, Jai Telengana or Jai Telengana and Jai Hind. The people's demand today is unequivocally for the Chief Minister and the present Ministers to step down. Their demand is that those leaders who have been arrested should be released from jail immediately and that President's rule should be imposed and a separate Telengana should be formed. But so far as a separate Telengana is concerned , we are aware, we have got to convince this horrible House and therefore it is not merely an emotional upsurge from our side that would cause that kind of conviction but the Members of this House must know the real facts of the Situation and therefore we have placed before the Government and before this House the demand that an opinion poll might be held in the Telengana region and if the opinion is in favour of a separate Telengana, then a separate Telengana State must come into existence.

Sir, the people are very sore about the situation as it exists today. I would like to place before this House the data that I have been able to collect from source like the news papers and some from the official sources. The facts, as it stands out, are extremely shocking. The struggle started in November last year. It is 10 months now and sometimes we begin to wonder in Hyderabad as to how this august House, in spite of two session, the budget session and this present session, has kept mum over the Telengana affair in this

weak manner. What are the facts? The facts are as follows:

The figure of deaths due to firing is 250. 18 deaths have happened due to lathi-charges. About 50,000 people have been arrested. The number of women arrested has come to 5,000 and the total number of persons arrested due to P. D. Act has come to 280. For 3,116 times the lathi-charges have taken place. The number of injured has come to 18,000. Of this, the number of blood injuries has come to 11,200. Number of fractures : one. Lathi-charge and bullet wounds : 1816. Number of times tear-gas shells used: 1850. Number of tear-gas shells used : above 11,200. These are the facts of Telengana. And therefore we would like to place before this House what is agitating our minds. If we got any sympathy whatsoever, if we obtained any sympathy from the responsible persons who visited us, it is to the Prime Minister to whom we are grateful. She is supposed to have come at mid-night. In spite of it she came there, she visited the hospital and wanted to see and enquire what was happening to the patients; and nobody else did it. There were 100 patients in the hospitals at that time. On learning that Prime Minister had come without notice and she wanted to visit the hospital 85 patients were compulsorily removed and sent home immediately and some of them having bullet wounds were also removed and only 15 were left for her to see.

One of the patients drew the attention of the Prime Minister to this fact. This is what happened at the time of her visit. Such incidents have happened throughout. I do not know whether in India today after independence such a mass movement has occurred where in each day about 15,000—20,000 people all over the districts courted arrest every day. This may have happened during the Quit India movement in 1942 when each State had contributed 30,000 or 40,000 people for satyagraha in 5 years. Here everyday, 15,000 men and 5,000 women were courting arrest everyday. These are facts.

And yet this was called an 'urchins' movement'. Now the Andhra Pradesh Government has said that it has spent or cost them Rs. 50 crores in suppressing the movement. Why this figure today? I cannot understand this figure?

An HON. MEMBER : On police?

DR. MELKOTE : The reason is that they wanted to deprive us of whatever surplus there is to be. If this loss has occurred, it is not because the Telengana people wanted this loss to occur. If this amount of Rs. 50 crores has been spent, it must be put squarely on the shoulders of the Andhra region, Budget expenditure not on us. We are not prepared to accept this or foot the bill. I want to make this very clear.

What are the facts ? Dr. Channa Reddy is supposed to have come here and attended the Congress Working Committee meeting when he was asked by a responsible member of the Working Committee : 'When the whole of India is trying to have integration, what is it you are asking for? Why are you asking for a separate Telengana ?'

Facts alone ought to be given here. I am grateful to hon. Shri K. L. Gupta. I am also grateful to hon'ble Acharya Ranga who has been espousing our cause. He has been doing it from the very beginning. Ever since the question of the formation of Vishal Andhra was mooted, he has been espousing our cause for a separate Telengana. It hurts us to part with our own brothers speaking the same language as we do. But what are the facts before us?

When the late Dr. Ramakrishna Rao was Chief Minister in the ex-Hyderabad State area there was firing in Bhongir and in Hyderabad over the question of merging with Andhra. His car was burnt. They wanted a separate Telengana. The movement was not focussed even then against Andhra. Then came in the gentlemen's agreement when the Andhra people said 'We are going to do this, we are going to do that for you'. We sincerely accepted all these tall promises. What has been the result ?

The result has been that in the engineering section of the PWD alone—I am voicing the problem before the Home Department for the past 10 years—this is the position regarding the question of reversion of Andhras in the gazetted ranks if justice to

[Dr. Melkote]

Telengana has to be done: 5 Chief Engineers, 19 Superintending Engineers, 120 Executive Engineers, 270 Assistant Engineers—all working in one department. Is this a small thing? Does it need 13 years to rectify the *inter se* seniority in one department?

This has occurred all over. I understand from the committee that met on the *inter se* seniority question, there were representatives of the officials in the gazetted ranks from the revenue department, the PWD, Co-operation and various other departments. When the Committee heard about this, they said, ' Is it impossible'?

These are facts. They were surprised at what is happening.

It has been said that there have been some killings and Andhras have been affected. We are extremely sorry if any one for Andhra has been killed or injured. But I would like to draw the attention of the House to what an amount of physical and mental suffering has been caused by this attitude of fist in a velvet glove policy of the Andhras on Telenganites for the last 13 years. Our monies have been diverted. Our *inter se* seniority has been affected. Our employment potential has been removed from us.

I would like to place before the House a document written by two Retired Chief Engineers and the third a Superintending Engineer of the Telengana area. They says that in the left bank canal of Nagarjunasagar which irrigates Telengana areas they have reduced the acreage and made arrangements of water to be more and more diverted over to the Andhra area. I shall place this document on the Table* later. Those things have been happening for thirteen years. Is it not a mass movement if 50,000 persons take part ? Then, if somebody questioned if this was the way to integration, it seems Dr. Chenna Reddi replied: I should like to know whether the definition of integration has got to be changed. We find that in another region, particularly in Bombay, the Shiva Sena has tried to oust Gujaratis, Andhras, Tamils and others. Here in Hyderabad, Gujaratis, Marwaris, Maharashtrians, Tamils, everybody is welcome, and even Andhras are welcome to stay. But we do not want colonisation of the Telengana area; we do not want to live like slaves under somebody else. We entered into a gentleman's agreement with them. After this experience of 13 years, we want separation. Now the Congress President comes and says: you have no majority with you. Whose majority ? When they wanted us to come together, it was the majority view of Telengana that they wanted to have. When we want separation, he speaks of the majority of Andhra, theirs is a two-thirds majority. They are the beneficiaries. Why do they want separation? If the Prime Minister has come out with an eight point formula, we are grateful. If Mr. Chavan has come and made no statement whatsoever—he said: I have got an open mind—we are grateful. But nothing has happened after that statement. We said: let us give him some time. Ministers at the Centre must study the situation. They say : what does it matter if a few hundreds of lives are lost? They do not mind, if people observe mass satyagraha and a section of the society gets killed like this. They talked of non-violence. In this connection, I wrote an article which was not published in every paper but some papers did publish it. In that article I said this on the 26th June.

"Leaders must enthuse all types. Selfless men and women of maturity, experience, wisdom and influence must also daily participate though their numbers may be small. The struggle must be organised to be continued endlessly. If this is ensured such men would safeguard our democracy, see to it that morally upright and unimpeachable and strong men of action man the affairs of future Governments. All the above can be achieved only if the movement is run on correct ideals of Mahatma Gandhi on non violent lines. This method alone in the long run, will achieve desirable results. Public life and property must be fully protected, particularly our National Railways. All Andhras and others are our own brothers and sisters. Maintenance of their dignity and honour should be the first concern of every Telenganite. Their

*Placed in Library. *See* No. LT—1928/69.

sympathies must be cultivated and one would welcome their participation in the Telengana cause."

The whole of the article has not been published but this is what I have said. The violence in the agitation has completely gone down and the effort is now to run it on non-violent means. Even during Mahatma Gandhi's non-violent struggles, violent incidents did take place. Nobody could exercise control over the actions of all persons. The Praja Samiti is there and each man is carrying on the struggle to the best of his ability. To the extent possible we are trying to control it and to a large extent violence has come down. But the mass upsurge is still going on and 4,000 men court arrest and two or three thousand women come forward from all the regions. B. Coms., LL. Ms., advocates and officers are all participating. I can give you hundreds of instances. This is the picture that I have got, and which I would like to place before the House. 280 people have been arrested under the PD Act. The Union Home Minister himself said that "We will not take action under the PD Act for political reasons." This was the assurance given to us. But what has happened? Out of those 280 people, three people were produced before the court. This is a very funny incident, and what was that? When they went to the court, it was pointed out that these men had given a speech in Sangareddi on such and such a date and they belonged to the Praja Samiti party. It was however proved that at that time the Praja Samiti itself did not exist. That is point No. 1. The second point is, it was pointed out that on account of the instigation of the Praja Samiti, such and such a cinema house was burnt down; but it was proved that nothing had been touched; not a hair was touched. The third thing was, they said that so and so gave a speech in Sangareddi, but then it was ultimately proved by alibi that he was in jail that day! All these cases went against the Government. Then they hurriedly approached the Chief Minister for withdrawing the case, and subsequently, they were allowed to withdraw the case. These are the things that take place there, and these were proved by the court itself.

There is another interesting story which I want to relate to you. Thousands of people offered peaceful satyagraha, many times. Whenever violence takes place, it is the so-called police who incite people either by beating or pelting the stones. I have seen it with my own eyes. The so-called accused are massed into the court-room. The advocates ask them, who are these people in Khaki police uniform but without identity number. They reply "The police." "Police ? They are not the police." They ask, "Where is your number ?" They reply "No numbers." Are the police department officers to engage goondas in police uniform but no identifying numbers to beat us down like this? Suppose, people want to provide themselves with khaki dress, and then go about in police dress, what are you going to do? Such people in police uniform are arresting and beating us down. I have got such pictures in hundreds. I have got pictures of such type of police beating the people down in large numbers. Every day, this is going on in Hyderabad, in the name of law and order. Who is to defend law and order ? Is it the police and the Government; or the people.

Supposing, they give instructions to the police, "All the cars to go without numbers from tomorrow." What are the Government going to do? Such things are occurring in Hyderabad, which are undreamt of. This is a democratic Government under the aegis of the Congress. Ram Rajya is expected to come, but I am afraid it will not be achieved by beating down the people.

I will give another instance. A lawyer pointed out to the magistrate in a court that the police without numbers may not belong to the police; thereupon the magistrate asked the person looking like a constable, "Where is your identifying number ?" The man picked out from his pocket some number and showed it to him !

Women satyagrahis are beaten down throughout the day. When I mentioned it to the Congress President, he said, "Why should at all the ladies participate in the satyagraha ?" Sir, the whole movement of freedom started with satyagraha, and our women were in the fore

[Dr. Melkote]

front and the fight went on. They wanted to democratise the administration, but after freedom, this is the situation that we find there, as against our past fight for freedom. We are not criminal law-breakers. Law-breaking is just symbolic. This is how the Government is going on there and this movement has been allowed to go on there for eight months.

Shri Kanwar Lal Gupta said that the Telengana problem should be settled soon, and asked "Cannot they stay with Andhras ?" But then, with the two-thirds majority always against our head, how can we ever achieve what we want ? The beneficiaries will always be in the majority and they will throttle our opinion. He asked, why do you want a separate Telengana? Don't you want to unite with the rest of India? Well, we do, and we do want to remain together, since we speak the same language, in Andhra. Many of the people belonging to other States have lived with us: Christians, Maharashtrians, Sikhs and so on. We have not said anything against them. Real integration has taken place in Telengana area what has taken place now is a complete crisis of confidence both in the Central and state Governments. When Dr. Channa Reddy was asked in the course of this agitation, "Are you integrationists, or are you dis-integrationists?" He said "we are the real integrationsits; and you are the disintegrationists." This is the situation in Andhra.

MR. CHAIRMAN : The hon. Member's time is up.

SHRI G. VENKATASWAMY (Siddipet) : Say about 15th of August.

DR. MELKOTE : Yes; 15th August this year. Section 144 was imposed on the 15th August. Nowhere has it been imposed since the past 20 years, on this day. But this time, in Hyderabad, it was imposed. Several people were beaten. One MLA, Sumitra Bai, was beaten black and blue for defying an order. She was bleeding and her clothes were full of blood-stains, at Hyderabad. The same thing occurred with regard to Shri Venkataswamy, M.P. who is sitting there. This is what is going on there.

Sir, this is the situation in Telengana. Come what may, this is a fight to the finish, so far as Telengana is concerned. One day, Telengana will come and it is bound to come.

16.00 hrs

SHRI M. N. REDDY : Sir, I want to submit only one thing. Notice has been given of a number of amendments. If they are moved, the hon. Members who participate in the debate will be in a position to comment on them, either support them or oppose them.

MR. CHAIRMAN : The amendments are already before the House.

SHRI M. N. REDDY : Some of them were not circulated on the ground that they were received too late. We were told that we will be permitted to move them during the debate. Unless they are circulated, members will not be able to comment on them.

MR. CHAIRMAN : They are going to be circulated immediately.

SHRI S. KANDAPPAN (METTUR) : Mr. Chairman, after hearing Dr. Melkote, who emotionally pleaded for a separate Telengana, I really do not know how to approach this problem. I am sorry that the Government of India vacillated for the last eight months in taking a decision and even today we do not know whether they are going to take some initiative and do something concrete to settle things in Telengana. All sections of the House were against the separation of Andhra and Telengana. Speaking for my group, we have said so on many an occasion. But I am sorry to say that the Government failed to take advantage of the co-operation of the opposition parties and they have missed the opportunity to arrive at consensus to settle this issue.

We know that it is a curious sort of agitation which is continuously being sustained for the past eight months. The agitation was started on a mass scale and we know for certain that there was no backing of any political party whatsoever at the time of starting the agitation. It was a popular agitation without any leaders. Probably,

afterwards the leaders tagged themselves on to the agitation in order to maintain their leadership, or to get the leadership which they did not have earlier. It would be minimising the importance of the popular sentiments if we still think, eight months after it was started, that the agitation was engineered by some disgruntled politicians or by some vested interests. It would also be minimising the importance of the problem if we feel that it can be equated with other demands for separation in other parts of the country. I feel this demand stands in a category by itself. Because, as we all know, before the formation of Vishal Andhra, Telengana was a separate entity. We also know for certain that the States Reorganisation Commission was not substantially in favour of the merger of Telengana with Andhra. Because we are sometimes inclined to forget it, I would like to quote the relevant portions from the report of the SRC. I am reading from paragraph 386;

> ".....it will be in the interest of Andhra as well as Telengana if, for the present, the Telengana area is constituted into a separate State, which may be known as the Hyderabad State, with provision for its unification with Andhra after the general election likely to be held in or about 1961, if by two-thirds majority the legislature of the residuary Hyderabad expresses itself in favour of such unification."

Then, para 388 says.

> ".....Andhra and Telengana have common interests and we hope these interests will tend to bring the people close to each other. If, however, our hopes for the development of the environment and conditions congenial to the unification of the areas do not materialize and if public sentiment in Telengana crystallises itself against the unification of the two States, Telengana will have to continue as a separate unit."

This is the observation of the States Reorganisation Commission.

After this, the people were taken into confidence by the leaders. They had faith in them and they agreed to that gentlemen's agreement. In the past 12 years with their bitter experience if they were not able to live together, is it not the responsibility of the Central Government or the State Government concerned to see how best they can be reconciled together, if at all the Government is keen about keeping them together?

This is a marriage of convenience and if after experience the parties feel that they have to divorce each other and if the Government intend on keeping them together, is it not the duty and the responsibility of the Government to see that they do something about it ? Otherwise, what is the use of allowing them to quarrel and continue the quarrel all these days?

It is impossible for us to reconcile the Government's responsibility *vis-a-vis* the continuous agitation that is going on there. The chronic indecision and inactivity on the part of the Centre is highly deplorable. Probably, due to political reasons the Government were not able to act very promptly. Even today I do not have much hope in the Government. Probably, they themselves do not know what will happen after the 20th of this month; so, they probably still waver and I do not expect any kind of a definitive answer from the Home Minister today. But I would like to appal to him and his Government that they should study the feeling of Members of the various sides of this House and try to understand and appreciate the realities of the situation.

I had occasion to enquire of the Home Minister whether by dividing the State or by creating an autonomous State within the State or by giving some more regional autonomous powers to the Telengana area, by any means, the Government is prepared to settle the issue and whether they can put an end to the violent situation that is prevailing there. The reply of the Home Minister was that every agitation had got its own life. I do not know what to make of that kind of a reply. The life seems to be very much protracted. Now there is prediction from every side that the life of the Congress is coming to a close. Therefore, at least before that eventuality happens, let them see that the life of the agitation in Telengana is put a stop to.

I know what difficulties and agonising situations the public has to go through in an

[Shri S. Kandappan]

atmosphere of an agitation. In this continuous eight-month agitation, I shudder to think what kind of agonies the common people, the women folk and the children, would have been going through. If the government of the day is not able to put an end to that agitation, can they really pride themselves that they are running a peaceful government and are having the law and order situation in their control ?

So, it is on that score that I would like to indict the Government and would like to plead with them that whatever decision they take, they should take it without further delay. There are many people on this side to support the decision that you take in the genuine interest of settling the issue. As a party we are already committed to the non-separation of Telengana but I am prepared to say that if it is inevitable and if the Government thinks that it cannot be averted, as far as we are concerned, we would not be creating any problem in the way of the Government. What we want is that the problem must be settled once for all and forthwith without further delay.

In this connection I would like to quote only one passage from an article which appeared in the *Hindu* dated July 1, 1969, and then I will conclude. I quote:

"Since politics is essentially an art and not a science, the Congress has evolved its own Theory of Relativity without apologies to Einstein to judge the rights and wrongs of various national problems in comparative terms to suit the party's immediate convenience, without attempting to look into any issue in its more fundamental context.

"But it is not possible in all circumstances to turn the art of politics into an art of evasion as well to avoid inconvenient decisions. And the law of immobility now paralysing the Congress thinking on problems like Telengana—involving high policy both at the national and State levels—has left little room for any imaginative initiative at the right moment to calm down passions and make the people realise the grave dangers of such extremism."

So, let the Government absolve itself at this late hour of its inactivity and I, genuinely, hope that they would attempt to do something to settle the issue.

Finally, I would like to say, though we are not so much emotionally involved as Dr. Melkote and some other Members from Telengana might be, we do feel very much concerned and agitated over the continuous agitation in one part of the country and that too in our neighbouring State. There is one lesson which I would like to draw from this. This is a kind of agitation which is an eye-opener to us, in a sense, that after Independence, this is the first time where it is definitely and conclusively proved that language is not after all such an unifying force. More than language, economic, cultural and social issues are very much involved in the unification of the country. This is for the protagonists of Hindi to member.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor) : Mr. Chairman, Sir, I come from Andhra area and not from Telengana area. It is unfortunate that this trouble has started. We wanted to live together as brothers and that is why we asked for Vishal Andhra and Vishal Andhra came into being.

Sir, unfortunately, some suspicion has come in the minds of Telengana brothers and that is why the trouble has started. The trouble was started first by the NGOs Association. That is how the trouble began. Whether they started trouble this way or that way, they were dissatisfied and they started the trouble. Later on, students joined the agitation and then politicians joined the agitation. Now, it has spread all over Telengana.

There is a feeling in Telengana that Andhra people are bossing over Telengana people.....

AN HON. MEMBER: Not the people; the Government there.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : There is a feeling that the Andhra people are illtreating them. That is their opinion. I would like to say here that if all the Telengana MLAs had come and joined together

and asked for the separation of Telengana, they would have got it. That is my opinion. But all the Telengana MLAs are not together. Some Telengana MLAs wanted a separate Telengana and the majority of Telengana MLA'S wanted integration. This is the position. For that, they cannot attribute any motive to the Andhra people.

We were very happy in Kurnool when we had a small Andhra State. Rayalaseema area was more backward as compared to Telengana. If you compare Telengana with Rayalaseema, Rayalaseema is more backward. In Telengana, at least they do not get famines. In Rayalaseema you get rain once in five years and for four years, you have to suffer. This is the position in Rayalaseema. Still we never opened our mouth. After the formation of Vishal Andhra, more money was diverted to Telengana area. But still they were not satisfied because they wanted more progress. They are not satisfied with the progress as expected by them. In every area, the people want to pogress. There is nothing wrong in Telengana people wanting to progress. I want Telengana people to progress and go forward. I do not object to that. The only thing is that for the last 8 months, the children have not gone to their schools and, for the last 8 months, there is trouble and in the offices, the NGOs are not working. There is no safety for ordinary people, be it the Telengana people or the Andhra people; there is no safety in the Hyderabad City today because whenever agitation comes—I do not blame the Telengana Praja Samiti—the unsocial elements also take over the situation and they do all sorts of things. I do not blame the Telengana Praja Samiti, but Government has to take action. I cannot blame the Government also. This is rather unfortunate.

The Telengana people suspect the Andhras; they say that most of the amount is spent in the Andhra area, they were taking away their surplus funds to the Andhra area. This is very unfortunate. But I have to tell one thing. I do not know the correct figures about the surpluses and how they have calculated and so on. But I want to point out one thing. In Vijayawada daily they purchase milk. This amount is debited to the Andhra treasury in Vijayawada. So, this goes to the debit of the Andhra people. Every day this milk is sold in Hyderabad and this amount is credited in the Telengana treasury. So, this comes as a surplus to the Telengana account. This is the position, even with regard to sales-tax and fertiliser tax. The factories and offices are in Hyderabad and this amount is credited in Hyderabad because that is the Capital, but that goes to the Telengana account and they say that this is their account and we have no credit for that. I am not saying anything here. Let them take even Rs. 10 crores more. But they need not accuse the Andhras who are living there. That is my appeal to them. To avoid all this suspicion, we have to settle it this way or that way. That is my opinion.

Our Prime Minister went to Hyderabad before she left on a foreign Tour—I think, for Japan. She rushed hurriedly to Hyderabad in mid-night. What decisions can we take in midnight? (*Interruption*) Unfortunately they are going in the wrong direction. After going there, she made sincere attempts to solve the problem; she met some politicians; it is very good, but one thing with which I cannot agree is this....

SHRI M.V. KRISHNAPPA (Hoskote): If one reads the proceedings, one will find that the British Parliament takes most of its important decisions in the dead of the night.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: This is the advice our people are giving and are thus spoiling everything.

SHRI M.V. KRISHNAPPA: We got Independence at 12, in the mid-night. (*Interruptions*)

श्री मधु लिमये (मुंगेर): वह मिड नाइट में ही काम करती है, पत्र भी मिड नाईट में लिखती है।

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: I object to only one thing. When the Prime Minister went there, she called, for consultation, the President of the NGOs Association who had been dismissed or suspended. I can understand if she discussed with poli-

[Shri Chengalraya Naidu]

ticians, but the Prime Minister has no business to discuss with such employees.. (*Interruptions*)

SHRI RABI RAY (Puri): Remove her.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: That is not a correct thing. If she wanted to consult them, she could send some officer from here to meet them. Now what has happened? Instead of solving the problem, she has appointed eight committees and Secretaries of Central Government are to preside over those Committees.

Actually 50% of Andhra Pradesh's autonomy has been transferred to the Centre. This is the position. Unfortunately...(*Interruptions*)

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur) : He has changed his loyalty. He is a turncoat.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : Sir, he is taking my time.

MR. CHAIRMAN : There is no reason for Mr. Lakkappa to get so much excited.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : Now, Sir, instead of having all this trouble, instead of having suspicion against one another, it is better for the Central Government—I appeal to them—to give a sub-State in the State of Andhra Pradesh on the lines of Assam Hill State. When two districts in Assam can get a sub-State, why not 9 districts of Telengana get a sub-State ? If the Government want to maintain the integrity of Andhra Pradesh, this is the only way for the Central Government to give a sub-State for the Telengana people. Let them manage their finances. Let them have their services. There would not be any trouble. There would not be any suspicion. This is the only way to solve the problem. I appeal to the Government to come forward to give them a sub-State.

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगूसराय) : सभापति महोदय, जब आन्ध्र और तेलंगाना की जनता ने अपनी एकता और संघर्ष के बल पर आन्ध्र राज्य की स्थापना की थी, उस वक्त हम लोगों ने हृदय से तेलगु भाषा-भाषी जनता का अभिनन्दन किया था और आज जब वही तेलगु भाषा-भाषी जनता आपस में लड़ रही है, आपस में विभक्त हो गई है, तो हम हृदय से दुखी हैं, हृदय से चिन्तित हैं। आखिर क्या कारण है कि जो तेलगु भाषा-भाषी जनता एक हो कर अपने प्रथक राज्य की स्थापना के लिये लड़ रही थी और जीती थी, आज वही अलग-अलग राज्य चाहती है। सभापति महोदय, सारी बातों को सुनने के बाद एक निष्कर्ष स्पष्ट है कि जिस आधार पर तेलगु भाषा-भाषी जनता की एकता स्थापित की गई थी, जिस आधार पर आन्ध्र राज्य की एकता की स्थापना की गई थी, उस आधार को आन्ध्र की सरकार ने नष्ट कर दिया। हम समझते हैं कि इस बात में शायद अब दो राये नहीं हैं। विभिन्न सूत्रों से जितनी भी बातें आई हैं, उन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो जैन्टिलमैन एग्रीमेंट हुआ था, उस का पालन नहीं हुआ और वही जैन्टिलमैन एग्रीमेन्ट दोनों क्षेत्रों की एकता का आधार था। उस का पालन न कर के उस एकता को नष्ट किया गया। मेरे पास समय नहीं है, वरना मैं इस बात को बतलाता कि किस तरह से वित्तीय साधनों के मामले में, किस तरह से नौकरियों और दूसरी चीजों में तेलंगाना के साथ अन्याय किया गया। उन को जो गारन्टी दी गयी थी, उस का उल्लंघन किया गया और इस तरह से ऐतिहासिक दृष्टि से आन्ध्र, तेलंगाना और रायलसीमा में क्षेत्रीय विषमता थी, वह न केवल कायम रही, बल्कि पिछले 13 वर्षों में और ज्यादा बढ़ी। सभापति महोदय, इस के लिये सिर्फ आन्ध्र की सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, केन्द्र में बैठी हुई यह कांग्रेस सरकार भी जिम्मेदार है। क्योंकि पिछले वर्षों में इस सरकार ने जो पूंजीवादी निर्माण का रास्ता अख्तियार किया, उस का नतीजा है कि पूरे देश में क्षेत्रीय विषमता बढ़ती जा रही है। सरकारी जिलों में और तेलंगाना के जिलों में बढ़ी, सरकारी जिलों और रायलसीमा के जिलों में बढ़ी, देश के दूसरे भागों में बढ़ी और आज इस हद तक बढ़ गई है कि सब आज महसूस करने लगे हैं कि इस विषमता

को दूर करने के लिये हम को कुछ न कुछ करना चाहिये ।

अब प्रश्न यह है कि आन्ध्र की इस क्षेत्रीय विषमता ने जो उग्र रूप धारण कर लिया है, उसको कैसे हल किया जाय ? आन्ध्र की सरकार अपने दमन के बल पर, पाश्विक दमन के बल पर, अमानुषिक दमन के बल पर इस समस्या को हल करना चाहती है । जाहिर है कि यह समस्या पाश्विक दमन के बल पर नहीं हल हो सकती । अभी करीब 200-300 लोग नज़रबन्द हैं । तेलंगाना की जनता जिसने अपनी समस्या को आपके सामने छेड़ा, उन को आपने जेलों में बन्द कर दिया है, तमाम स्कूल-कालिजिज़ बन्द पड़े हैं···

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य (रायगंज): ज्योति बसु ने तो हजारों को नज़रबन्द कर दिया था ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : ज्योति बसु के बारे में तो बंगाल की जनता ने फैसला दे दिया ।

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य: पुलिस ने दिया है, जनता ने नहीं दिया ।

श्री योगेन्द्र शर्मा: जिन लोगों को तेलंगाना की जनता ने अपने कन्धों पर चढ़ाया उन को नज़रबन्द कर के क्या आप आन्ध्र की समस्या को हल करना चाहते हैं ? क्या इस तरह से वह हल हो सकती है ? कैसे हल कर सकते हैं ? क्षेत्रीय विषमता की जो समस्या है, वह ऐसी समस्या है, जिसको राजनीतिक आधार पर आर्थिक आधार पर हल करना पड़ेगा । इस लिये हम समझते हैं कि इस समस्या को हल करने के लिये न केवल ऐसा कानूनी और वैधानिक कदम उठाना पड़ेगा ताकि क्षेत्रीय विषमता को हम दूर कर सकें, बल्कि ऐसा राजनीतिक वातावरण भी कायम करना पड़ेगा, जिसमें हम इस चीज़ को कर सकें । इस के लिये हम सब से पहला और आवश्यक कदम यह समझते हैं कि जो भी दमन किया गया है या किया जा रहा है उस को तुरन्त बन्द किया जाय । जिनको नज़रबन्द किया गया है उन को अविलम्ब और बिना शर्त रिहा किया जाय । जब तक यह नहीं होता है तब तक समस्या के समाधान के लिये एक राजनैतिक वातावरण नहीं बन सकता ।

दूसरी चीज़ जो बहुत ही आवश्यक है, वह यह है कि बदकिस्मती से आन्ध्र और तेलंगाना के बीच--जैसा कि हमारे गुप्ता जी ने कहा है—अविश्वास की एक दीवार बन कर खड़ी हो गई है । अविश्वास की इस दीवार को ढाना होगा और इस को ढाने के लिये आवश्यक है कि आन्ध्र में जो सरकार है, उस को हटाया जाय और उस को हटा कर आन्ध्र और तेलंगाना की जनता के प्रतिनिधियों को बैठा कर एक गोलमेज सम्मेलन कर के इस समस्या को हल करने का निर्णय करें । यही एक रास्ता है, जिस पर चल कर हम क्षेत्रीय विषमता से पैदा हुई इस समस्या को हल कर सकते हैं । इस के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता घातक रास्ता होगा । हम को अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि विभिन्न कारणों से इस रास्ते को अब तक नहीं अपनाया गया । लेकिन यदि इस रास्ते को नहीं अपनायेंगे तो आन्ध्र की समस्या हल नहीं कर सकते हैं, न केवल आन्ध्र की समस्या, बल्कि इस तरह की समस्याओं का सामना आपको देश के दूसरे भागों में भी करना होगा ।

मैं शुक्ला जी को कहना चाहता हूं--आपकी ही सरकार के एक मंत्री ने बिहार के एक विशेष भाग में जाकर पिछले महीने एक भाषण किया है कि मिथिला राज्य के रूप में एक पृथक राज्य की स्थापना होनी चाहिये । मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने सही कहा है या गलत कहा है, जब इस पर विवेचना का वक्त आयेगा, तब विवेचना करूंगा, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज क्षेत्रीय विषमता की समस्या इतनी बढ़ गई है कि उस से आंख बन्द नहीं की जा सकती । हम को कहा गया है कि नौकरियों की गारन्टी

के पालन में संविधान बाधा है, हमारे हाथ और पैरों को रोकता है, 300 रु० की नौकरियों से कम तनख्वाह वाली नौकरियों पर सिर्फ तेलंगाना के लोग ही बहाल हों--संविधान इस की इजाजत नहीं देता है। अगर संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है तो क्या क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए जो दूसरे कारगर कदम हैं, उन को नहीं उठाया जा सकता। ऐसी दलील दूसरी जगहों के लिये भी हम ने सुनी, बिहार के कुछ हिस्सों में जहां नये कारखाने बनाये जा रहे हैं, जिन लोगों ने जमीनें दी हैं, घर दिये हैं, वे जब कहते हैं कि चौथी श्रेणी की नौकरियों के लिये उन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए--तो कहा जाता है कि संविधान इस की गारन्टी नहीं देता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय विषमता को हल करने के लिये, संविधान में अब तक संशोधन कर लेना चाहिये था। देश की एकता और राज्यों की उन्नति के लिये यह सब से बड़ा तकाजा है। यदि आपने ऐसा नहीं किया, ऐसी ही अवस्था बनी रही तो आप अलग राज्य के निर्माण की बात नहीं रोक सकते हैं यदि आपने कांस्टीट्यूशनल गारन्टी नहीं दी तो आप अलग तेलंगाना राज्य की स्थापना को नहीं रोक सकते हैं।

इसलिए मैं तेलंगाना के भाईयों से, आंध्र के भाइयों से, तेलुगु भाषा-भाषी भाइयों से अपील करना चाहूंगा कि आप मेरे सुझाव पर विचार करें क्योंकि मेरे सुझावों पर चल कर के ही तेलुगु भाषा-भाषी एकता की रक्षा हो सकती है और क्षेत्रीय विषमता का जो कोढ़ हमारे समाज और राष्ट्र में पैदा हो गया है उसको दूर किया जा सकता है।

MR. CHAIRMAN: I have a number of names of speakers before me, specially those from Telengana. I should like to give chance to as many members as possible but they should be as brief as possible because we have to finish at 5-30 P.M.

SHRI M.N. REDDY: I beg to move:

"That in the motion—

for "urges upon the Government to take necessary steps"

substitute—

"requests the Speaker to appoint a Committee of the House consisting of 21 members to make an on the spot study of the situation and suggest appropriate measures for a just and practical solution of the problem." (2)

SHRI M. V. KRISHNAPPA: I beg to move:

"That at the end of the motion, the following be added, namely :—

"and to appoint a high power Commission on the lines of the States' Reorganisation Commission to advise the Government within a period of one year."(5)

MR. CHAIRMAN: These amendments are also before the House.

श्री जी० वेंकटस्वामी (सिद्दिपेट): अध्यक्ष महोदय, मैं तेलंगाना से आता हूं इसलिए मैं हमेशा हिंदी में ही बोलने की कोशिश करता हूं। यहां पर मैं बहुत जख्मीशुदा हूं। शायद सारे मेम्बर्स जानते हैं कि ब्रह्मानन्द रेड्डी की पुलिस की गोलियों से जख्म खाये, पुलिस ने मुझ पर जितने जुल्म किये, गोली चलाई उसके बाद मरते-मरते बचकर इस पार्लमेन्ट हाउस में तेलंगाना की आवाज को लेकर पहुंचा हूं। · · · (**व्यवधान**) · · · अब मैं जय तेलंगाना के साथ अपना भाषण शुरू करना चाहता हूं। जय तेलंगाना, यह मेरी आवाज नहीं है। जय तेलंगाना, तेलंगाना के 9 डिस्ट्रिक्ट के एक करोड़ 7 लाख इनसानों की आवाज है, जिसको मैं पहली मर्तबा इस पार्लमेन्ट के अन्दर रखना चाहता हूं। इस बहस में कुछ मेम्बर्स ने यहां पार्टिसिपेट किया

है। सारे लोगों में इस मसले को एक पैचीदा मसला समझा जा रहा है। लेकिन यह मसला तेलंगाना के लोगों की वजह से पैचीदा नहीं हुआ। जब आन्ध्र प्रदेश फार्म हो रहा था और फजल अली रिपोर्ट आई थी, उसके बाद ही एजिटेशन शुरू हुआ था। वहां के लोगों ने यहां सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट को रिप्रेजेन्ट किया था कि आप हमारे को आंध्र के साथ मत मिलाइये क्योंकि हम बैकवर्ड हैं, हमारे डिस्ट्रिक्टिस और गांव बैकवर्ड हैं, उनके साथ मिलायेंगे तो हमारा नुक्सान होगा। कमीशन ने यह बात स्पेसिफिक लिखी थी कि सन् 56 तक आंध्र के साथ रहिये। अगर उसके बाद तेलंगाना की दो तिहाई मेजारिटी नहीं चाहती तो अलग स्टेट बन सकती है। इन 12 सालों में आन्ध्र गवर्नमेन्ट की तरफ से जितने जुल्म किये गये, तेलंगाना के लोग उन जुल्मों को सहते चले आ रहे हैं। अगर आज कोई कहता है कि तेलंगाना के लीडर्स की आवाज़ है तो मैं साफ कहना चाहता हूं कि यह कोई पोलिटिकल लीडर की आवाज़ नहीं है बल्कि लीडर्स जो एजिटेशन कर रहे हैं, उनकी शरण लिए हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह आवाम की आवाज़ है। मैं खुद आन्ध्र प्रदेश इंटिग्रेशन कमेटी का 6 महीने तक चेयरमैन रह चुका हूं। हमने ब्रह्मानन्द रेड्डी के कहने पर जुलूस निकाले कि हम इन्टिग्रेशन में रहेंगे, मिलकर रहेंगे लेकिन पब्लिक और गांव-गांव से यह आवाज़ आई कि अब सिवाय सेप्रेट तेलंगाना के ओर कोई चारा नहीं है इसलिए कि इन लोगों ने हमारे साथ बेइमानी की है। जब आन्ध्र प्रदेश फार्म हुआ था तो एक जेंटिलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था, उस जेन्टिलमैन्स एग्रीमेन्ट में यह साफ-साफ बताया गया था कि हम आपको सेफगार्डस देंगे--सेफगार्ड यह है कि वहां के लोगों को मुल्की सर्टिफिकेट के साथ एम्पलायमेंट देंगे। लेकिन आंध्र के मिनिस्टर्स ने हजारों की तादाद में ला लाकर लोगों को भरा है और वहां के हजारों लाखों स्टूडेन्ट्स जो निकलते हैं उनको एम्पलायमेन्ट नहीं मिलता है।

16.36 hrs.

[SHRI M. B. RANA *in the chair*

ऐसी हालत में हम क्या करें? इस आज़ाद देश में, आन्ध्र प्रदेश में फख्र के साथ रहने के बाद भी वहां के रहने वालों को उद्योग नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती जबकि गैर मुल्की सर्टिफिकेट लेकर नौकरी ले लेते हैं। यही बात नहीं है, स्टूडेन्ट्स आज इसलिए भड़क उठते हैं क्योंकि वे कहते हैं हम क्या करें, हम पास हो चुके हैं, हमारे लिए नौकरी नहीं है और आन्ध्र से जो सर्टिफिकेट लेकर आते हैं उनको नौकरी मिल जाती है क्योंकि उनके लिए मिनिस्टर साहब का टेलीफोन हो जाता है।

दूसरी बात यह है कि सर्विसिज़ के जितने केसेज़ हैं--श्री कंवरलाल गुप्त और रंगा जी ने जैसा बताया वह बिल्कुल सही है--कि हजारों की तादाद में एम्पलाईज़, डाक्टर्स, इंजीनियर्स, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले हजारों लोगों के केसेज़ यहां पर आये हैं लेकिन 13 सालों में कोई फैसला नहीं हुआ है। इससे बड़ी बेचैनी फैली हुई है लेकिन कोई सैटिलमेन्ट नहीं हुआ।

तीसरी बात यह कि आंध्र प्रदेश के फार्म होते समय यह बताया गया था कि तेलंगाना तो "बैकवर्ड एरिया है, हम ज्यादा-से-ज्यादा फंड्स तेलंगाना पर खर्च करेंगे। हमने भी इत्मीनान किया कि आंध्र गवर्नमेन्ट बोलती है कि हमारा फायदा करेगी लेकिन 13 साल के अन्दर दो सौ करोड़ रुपया बैकवर्ड तेलंगाना से लेकर आन्ध्र पर खर्च करने के बावजूद हमसे कहती है कि खामोश बैठो। एक तरफ तो वायदा किया गया था कि तेलंगाना पर ज्यादा-से-ज्यादा खर्च करेंगे लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने बेइमानी की है। इसके बाद वहां के स्टूडेन्ट्स, किसान, नौजवान, मजदूर सारे ही लोग सोचने लगे कि अब हमारी सेफगार्ड्स चाहिए, कम-से-कम सेफगार्ड्स कर दी जाय। जनवरी में चीफ मिनिस्टर ने आल पार्टीज़ मीटिंग बुलाई जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतन्त्र पार्टी सभी लोग

आये और उन्होंने दस्तख्त किए कि सारे-के-सारे इम्पलीमेन्ट करेंगे। पब्लिकली चीफ मिनिस्टर ने प्रेस के सामने एनाउन्स किया है, प्रेस के सामने कि हमसे गलती हुई है, हम उसको दुरस्त कर लेंगे। मैं साफ कहना चाहता हूं कि अभी भी जो कह रहे हैं कि सेप्रेट नहीं होना चाहिए, उनसे मेरी नम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि 8 महीने हो गए हैं, सारी पार्टीज़ के दस्तखतों के साथ, अपोजीशन के लीडर्स के दस्तखतों के साथ जो अपील निकली थी इम्पलीमेन्ट करने के लिए, क्या उसमें एक को भी इम्पलीमेन्ट किया गया है। नहीं कर सकते ये लोग। मुल्की रूल को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने रेजैक्ट कर दिया है। और दो सौ करोड़ रुपया तेलंगाना का आंध्र पर खर्च किया गया है उसको कुछ कमेटीज़ ने पेंडिंग में डाल रखा है। तो जितना छीनना है छीन लिया, जितना दबाना है दबा लिया और जबान से कहते हैं कुछ नहीं किया। एजिटेशन किया जाता है तो कहते हैं कि वायलेन्स करते हैं। मेरी नम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि हमारे तेलंगाना का रिवाज है, अगर पूरा हिन्दुस्तान आप देखना चाहते हैं तो हमारे पास सारे हिन्दुस्तान के लोग हैं, अमन से हैं उनको कोई शिकायत नहीं है, तेलंगाना के लोग किसी को भी बाहर जाने के लिए नहीं कहते हैं। हम कभी भी नहीं कहेंगे। हम किसी आन्ध्रा भाई को जाने के लिये नहीं कहेंगे। मगर यह बात सत्य है कि अगर कोई पोलिटिकल लीडर जा कर कहता है कि सैपरेट तेलंगाना नहीं होगा तो आवाम इसको नहीं मानेगा। हम सेप्रेट तेलंगाना चाहते हैं। शादी का आधार मियां-बीबी का विश्वास होता है। लेकिन जब कानफ़ीडेंस ही चला गया और जब दस्तूरी तौर पर तलाक देने का हक है तो उस से हम कोई नहीं रोक सकता। हमने ऐग्रीमेंट के साथ अपनाया लेकिन अब इन के ऊपर से हमारा कानफ़ीडेंस चला गया है और सरकार जबरदस्ती रखना चाहती है यह मुश्किल है। कानफ़ीडेंस खत्म हो गया इसलिये मिल कर रहना मुश्किल है।

चीफ़ मिनिस्टर साहब ने वायदा किया कि जितने भी सेफ़ गार्ड्स हैं उन पर अमल करेंगे। गवर्नमेंट के अन्दर रहने वाले मिनिस्टर, कांडु लक्ष्मण जी बापू ने चीफ़ मिनिस्टर से कारस्पौंडेंस किया और कहा कि उन सेफ़-गार्ड्स पर जल्दी से जल्दी अमल कराइये। लेकिन चीफ़ मिनिस्टर ने अमल नहीं कराया क्योंकि वह नहीं कर सकते, प्रोब्लम्स, ऐसी हो गयी हैं कि वह नहीं कर सकते। इसलिये लक्ष्मण जी बापू ने रिजाइन कर दिया रिजाइन करने के बाद आज उन को राज-मुन्धरी जेल में रखे हैं। अगर चंचलकोंडा जेल में रहें तो सरकार को डर है कि लोग उन से मिलेंगे। इसलिये राज मुंधरी जेल में रखा। डा० चेन्ना रेड्डी को तथा और जो लीडर्स हैं, एम० एल० एज़० हैं उन सब को दो महीने से जेल में रख रखा है इसलिये कि सरकार को डर है कि अगर ये लोग वापस आ जायेंगे तो तेलंगाना मूवमेंट बढ़ जायगा और ब्रह्मानन्द रेड्डी को मुश्किल हो जायगा रहना। हम ने होम मिनिस्टर से कहा कि क्या हैदराबाद की जेल खराब है ? क्या पी० डी० ऐक्ट के लोगों को वहां नहीं रख सकेंगे ?

मैं दर्दनाक चीजें आप को बताना चाहता हूं। अभी डा० मेलकोटे साहब ने बताया कि आजाद हिन्दुस्तान में 50 हजार से ज्यादा लोगों का अरेस्ट होना और हमारे पार्लियामेंट में मेम्बर खामोश बैठें, यह कैसे सम्भव है। हजारों औरतें सत्याग्रह में जेल में गयीं। जेल के अन्दर जो सत्याग्रही थे, ब्रिटिशर्स के समय में भी ऐसा नहीं हुआ होगा, जो निहत्थे बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, उन को जेल के अन्दर चोरों से पिटवाया गया। इस को देखने के लिये मैं गया। किसी का हाथ टूट गया, किसी की आंख फूट गयी, किसी की कमर टूट गयी। अगर सरकार समझती है कि लाठी और गोली से इस मूवमेंट को दबा

देंगे, तो मैं समझता हूं कि वह गलती करती है, तेलंगाना के नौजवान इस को मानने के लिये तैयार नहीं हैं ।

मैं कहना चाहता हूं कि श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी को आज जाना चाहिये और किसी न किसी तरह से तेलंगाना के आदमी को चीफ़ मिनिस्टर बनाना चाहिये । ब्रह्मानन्द रेड्डी या उन का कोई एजेन्ट तेलंगाना का चीफ़ मिनिस्टर बना तो वह तेलंगाना की प्रोबलम हल नहीं कर सकता क्योंकि वहां के हजारों नौजवान, किसान, मज़दूर इस मूवमेंट के अंदर इनवाल्व हो चुके हैं, उन लोगों को सजायें हो चुकी हैं । 200 इन्सान गोलियों का निशाना बन चुके हैं और हम लोग पार्लियामेंट के अन्दर बैठ कर यह सोचें कि किस तरह से दोनों को मिलाना चाहिये, यह सम्भव नहीं है, समस्या का हल इस तरह से नहीं होने वाला है । आज घर-घर के अन्दर से यह आवाज़ निकल रही है कि हम नहीं मिल सकते ।

चव्हाण साहब का नाम वहां के चीफ़ मिनिस्टर लेते हैं और कहते हैं कि मेरा क्या है, मैं तो तेलंगाना के लिये तैयार हूं, आप के चव्हाण साहब ही तैयार नहीं हैं क्यों कि उन को विदर्भ का डर लगा हुआ है । निजलिंगप्पा को डर इसलिये लगा हुआ है कि वह मैसूर के हैं और मोरार जी देसाई को डर इसलिये है कि उन को सौराष्ट्र का डर है । यह अवाम की आवाज है । यह तेलंगाना से निकल कर विदर्भ, सौराष्ट्र और मैसूर को जाती है कि कोई कुव्वत इस आवाज को रोक नहीं सकता । तेलंगाना को देना ही पड़ेगा । इस वास्ते कि अवाम के अन्दर से यह आवाज निकल चुकी है कि हम ने कहा था कि मिल कर चलायेंगे, मिला कर देखेंगे । लेकिन हम ने देखा कि मिल कर नहीं चल सकते हैं । जब मिल कर नहीं चल सकते तो तेलंगाना देना ही पड़ेगा ।

जो निहत्थे लोगों को मारा गया है उस के लिये एक कमिशन बनाया जाना चाहिये होम मिनिस्टर की तरफ से । आज आप देखिए कि हैदराबाद सिटी में कितनी सेंट्रल पुलिस रक्खी हुई है ? हम ने होम मिनिस्टर के सामने यह रिप्रेजेन्ट किया कि रोजाना एक लाख रुपया तेलंगाना मांगने वालों के खिलाफ खर्च हो रहा है । पिछले आठ महीनों में 15 करोड़ रु० खर्च हो चुके हैं । जब हम होम मिनिस्ट्री से कहते हैं तो यह जवाब मिलता है कि उस को नक्सलवाड़ी वालों के लिये रक्खा गया है । लेकिन आज 10,000 पुलिस सिर्फ हैदराबाद सिटी के अन्दर इस्तेमाल हो रही है । जो भी सामने आता है, औरत, मर्द, सबों को मारना शुरू कर देते हैं । जिस बुरी तरह से उन को मारा पीटा जाता है, उस को मैं बयान नहीं कर सकता ।

तेलंगाना में आठ महीनों से स्कूल बन्द हैं । कई बार तेलंगाना बन्द रह चुका है, दूकानें वगैरह सब । नो विज़िनेस । वहां विज़िनेस का नाम नहीं है, ला ऐंड आर्डर का नाम नहीं है । इस के बावजूद हम से कहा जाता है कि हम मिल कर रहना चाहते हैं । अब यह होने वाली बात नहीं है । आज तेलंगाना के एक-एक मर्द, औरत, नौजवान, मजदूर, किसान सब लोगों की आवाज है कि तेलंगाना हो कर रहना चाहिये । मेरी सभी लोगों से, अपोजीशन वालों से भी विनम्र प्रार्थना है कि वह इस मामले को कंसिडर करें । 200 आदमियों की बलि चढ़ी है । आज 200 मरे हैं, कल 2,000 मरेंगे, लेकिन तेलंगाना ले कर रहेंगे । यह आज आवाज तेलंगाना वालों की है जिस को मैं आप के सामने पेश करना चाहता हूं । मैं जजबात में आ कर यह बात नहीं कर रहा हूं । आज तेलंगाना वालों में जोश है, उन में जजबात हैं, अब वह साथ नहीं रह सकते । बारह साल तक साथ रह कर देख लिया है । अब साथ नहीं रह सकते

हैं, इस लिये तेलंगाना अलग किया जाय । जय तेलंगाना ।

SHRI M.V. KRISHNAPPA: Sir, members belonging to adjoining States, like Mysore, should also get an opportunity.

SHRI P. GOPALAN (Tellicherry): Sir, while we are hearing vociferous arguments both for and against the formation of a separate Telengana State, some others have argued for autonomy of Telengana within the united Andhra State. Both these arguments are based on the same theme, namely, that injustice has been done to the people belonging to Telengana by the non-implementation of the so-called Gentleman's Agreement which was entered into between the Congress leaders of Telengana and Andhra Pradesh some years back. They give this as the real reason for the backwardness of the Telengana region.

I do not think this argument has much relevance in this context, because ours is a backward country. I come from an area which is very much backward as compared to other areas in my State. But how will it look like if I demand a separate State for my area on the ground that it is backward? I would like to have an answer to this question from the protagonists of a separate Telengana, who want it on the ground that Telengana is a backward region because it was part of the United Andhra State.

It is true that Telengana is a backward area. That is the result of 22 years of Congress rule in this country.

Unequal economic development is inherent in Indian society. So long as the capitalist social order is there this unequal economic development is bound to take place. So, there is no question of the liquidation of this backwardness by granting a separate Telengana State. So, we have to find out the real reason for this movement. How this movement has been utilised by some of the interested parties is the basic issue.

There is large-scale misery for the people of Telengana. There is growing unemployment. The people there are disappointed and dejected. This disappointment, fury and the legitimate grievances of the people are exploited by a section of politicians. The people are misled. They have deliberately been exploited. The people, who speak the same language, who have the same culture and who have the same personality, are fighting against each other, like brothers, in the Andhra State. That is a strange feature that we see in that area.

Some people are posing themselves as the champions of the people of Telengana. I remember the heroic incident of some 20 years back when the lion-like people of Telengana fought like lions. At that time the protagonists, the so-called champions, of the Telengana movement were indulging in mass scale violence and butchery of the people of Telengana. Now they are posing as the champions of the people.

What have the Congress leaders been doing all these years? For 22 years they have been enjoying power. Some of them are occupying important places in the Andhra Cabinet. Why did these people not raise a single finger against this injustice that was being done to the people of Andhra Pradesh ?

My party is very definite in this respect. There is no question of a separate Telengana State. We are totally opposed to it. If such a tendency is allowed to grow, there will be claims or demands for other States. A claim may come for a Vidarbha State or for a division of Mysore State. These slogans have already been raised.

My party has put forth certain proposals about how this is to be solved. This can be solved if the people of Telengana are won over from the clutches of the so-called political leaders of that area. They have been misled. Many of them are pro-landlords and pro capitalists. These leaders are misleading the people. So, the people have to be won over. Some radical measures have to be taken over by the Government. Land reforms have to be brought about and landlordism has to be liquidated in Andhra Pradesh. The people have to be won over from the clutches of landlords and capitalists.

Lastly, why are the Birlas so much interested in the Telengana issue? I can tell you that workers working in the Allwyn Company controlled by the Birlas were regularly paid their daily wages and were allowed by the management to go and participated in the struggle. Why? Why is Birla interested so much in that affair ?

I would like to say that some interested people are behind the movement. Some landlords, some capitalists, Birlas and some vested interests are behind the movement for their own purposes. So, I wish to say that this movement is being misled and the people are being misled. Certain measures are to be taken so as to make some transformation in the social order and also some radical agrarian reforms have to be made. Then only you can win over the people and keep intact the unity of the people of Andhra Pradesh.

SHRI M.N. REDDY: Sir, with your permission, I move that the time on this debate be extended by 2 hours.

It will be a great injustice to give 5 minutes to each Member on an important subject like this .

SHRI YASHPAL SINGH: (Dehra Dun): The time should be extended by 2 hours.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

SHRI M.N. REDDY: Last time, 4 hours were allotted to it. The House sat upto 9-30 P.M. and the Home Minister replied to the debate the next day.

The hon. Home Minister is not present here. We are not prepared to speak without his hearing our speeches. Mr. Vidya Charan Shukla is sitting here and if he is replying to the debate, we do not mind speaking. But the Home Minister is going to reply to the debate. He should be present here. He should hear not only the speeches but the sentiments with which the speeches are made.

MR. CHAIRMAN: Let us see how we progress.

SHRI M.N. REDDY: You take the sense of the House. My motion is there. You may put it to the House.

MR. CHAIRMAN: Let us see how we progress. Instead of 5 minutes, I will allow 7 minutes each.

SHRI M.N. REDDY: That is not enough. I have moved the motion. That motion may be taken up and put to the House.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapura): The motion is there. It is that the time may be extended by 2 hours. You take the sense of the House. I do not say we should sit late. We can take up the Half-an-Hour discussion at 5-30 P.M. and continue this discussion tomorrow.

SHRI M.N. REDDY: We can continue tomorrow.

MR. CHAIRMAN: The Speaker has said that he will allow half an hour more. I cannot exceed that.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Let us adopt the motion moved by Shri M. N. Reddy and continue the discusssion tomorrow.

MR. CHAIRMAN: Mr. Reddy, your motion is there but you have to obtain the Speaker's previous permission to move the motion.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY: The Chair is there.

SHRI M.N. REDDY: You are the Speaker for all purposes now.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY: You can take the sense of the House.

16.59 hr.

[MR. SPEAKER *in the Chair.*]

SHRI M.N. REDDY: Mr. Speaker, Sir, have moved a motion that the time of the discussion on Telengana be extended by 2 hours. That motion is there. The whole House is unanimous on that. We can continue the debate tomorrow. Last time, we discussed it for two days and the House sat late also. This is an important subject. The Minister of Parliamentary Affairs is there. He may agree.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH): It is all right.

MR. SPEAKER : The question is :

"That the time on this Debate be extended by two hours."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER : If you had asked for more, I think, even that much he would have agreed. So, we will continue the discussion upto 5-30 P.M. and take up the Half-an-Hour Discussion at 5-30 P.M. Then, we will continue the discussion on Telengana tomorrow.

श्रीमती लक्ष्मीबाई (मेडक) : अध्यक्ष महोदय, अभी कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य ने कहा है कि हैदराबाद को विशालांध्र में ही रहने देना चाहिये। मैं समझती हूं कि उन को हैदराबाद की स्थिति के बारे में मालूम नहीं है। हैदराबाद में सब भाषाओं के बोलने वाले रहते हैं, जिन के दादा-परदादा वहाँ रहते थे, जो वहां पैदा हुए हैं और जो वहां ही मरेंगे। दिल्ली और देश से सब स्टेट्स से हमारा बहुत सम्बन्ध रहता है। हम सेप्रेट तेलंगाना इस लिए मांगते हैं कि प्रजातंत्र में राज प्रजा के पास होना चाहिए। प्रजा-राज का यही अर्थ है। प्रजा-राज का अर्थ यह नहीं है कि प्रजा का नाश कर के, प्रजा के हितों को नुक्सान पहुंचा कर प्रशासन चलाया जाये। आप लोग समझिए। यह कम्यूनिस्ट लोग आज कह रहे हैं कि सेपरेट तेलंगाना हम नहीं चाहते, मैं कहती हूं कि इस में सेपरेट तेलंगाना की बात कहां है, हमारी हैदराबाद स्टेट तो पहले से ही सेपरेट स्टेट थी, जिस में हरएक भाषा बोलने वाले लोग शरीक रहे हैं, और वहां पर हरएक चीज हमारी मौजूद रही है। यह लोग हम को पालिटिक्स सिखाना चाहते हैं। मैं इन से कहना चाहती हूं कि हम इन से पहले पैदा हुए और पालिटिक्स इन से ज्यादा समझते हैं। यह कम्यूनिस्ट लोग जो हैं इन की बातों को हम अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन मैं इस समय उस बहस में नहीं जाना चाहती। हमारी हैदराबाद स्टेट सैकड़ों साल से भारतवर्ष में एक अलग स्टेट रही है। सेपरेट हैदराबाद हमारा हमेशा से रहा है। इस में हमारा मिंट है, रेलवे है, यूनिवर्सिटी है सब कुछ पहले से मौजूद है। यह तो पिछले 12-13 साल से दूसरे लोगों को हमारे साथ मिला कर हमें ज्वाइंट बना दिया है, वरना हम तो पहले से ही सेपरेट चले आ रहे हैं। इस में कन्नड़ महाराष्ट्र और तेलुगु तीन भाषा बोलने वाले लोग थे। उस में से कन्नड़ वालों को अलग मैसूर के साथ कर दिया, महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र के साथ चले गए रह गए केवल तेलंगाना वाले जिन के साथ आन्ध्र वालों को ला कर ऊपर से लाद दिया। फिर भी हम लोग चाहते थे कि ठीक है, लेकिन 12 साल का तजरबा हम ने देखा उस में हमारे साथ किस तरह का बर्ताव किया गया। यहां से एम० पीज० गए, देख कर आए, चव्हाण साहब जा कर देख लिए, प्रधान मंत्री भी देख कर लौट आई, और फिर सब चुप बैठे हैं। अभी यहां पर डा० मेलकोटे साहब बोले, वेंकटस्वामी बोले और कुछ एम० पीज० भी बोले। हमारा 117 करोड़ रुपया यह लोग ले गए। वह कैसे मैं बताती हूं। ऐसा है कि वहां पर ताड़ी और अफीम बहुत होती है। आन्ध्र में प्राहीवीशन है, लेकिन तेलंगाना में तो प्राहीवीशन नहीं है। तो उस के ऊपर ५ से लेकर 10-12 करोड़ तक रुपया मिलता है। वह पैसा तमाम दूसरे रीजन पर खर्च किया गया। यह मैं आन्ध्र गवर्नमेंट के लिए कह रही हूं, आन्ध्र के लोगों के लिए नहीं कह रही हूं। और इस के अलावा आते ही शुरू-शुरू में 13 करोड़ रुपये निजाम हैदराबाद के सेक्योरिटी में रहते थे वह भी रह लोग बेच डाले हैं। तो आते ही इस तरह हमारे ऊपर इन्होंने यह व्यवहार किया। इस के पहले प्रिंसेज स्टेट जब थीं तो आप जानते हैं कि वहां रेवन्यू ज्यादा लिया जाता था और गरीब लोगों के ऊपर कोई

तवज्जह नहीं दी जाती थी, तो हमारे यहां के लोगों के डेवलपमेंट पर उस समय भी कुछ खर्च नहीं होता था और फिर जब यह लोग आए तो उस के बाद भी हमारे डेवलपमेंट की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह भी एक प्वाइंट है। अभी कुछ पढ़ाई वहां शुरू हुई है तो पढ़ने के बाद उन को मुलाज़मत कहीं नहीं मिलती, इस से भी उन के अन्दर बेचेनी बढ़ती है। दूसरा प्वाइंट यह भी है कि हमारे एम० एल० ए० जो होते हैं उस में अधिक से अधिक यह अपने लोगों को टिकट देते हैं, वहां के भी उन्हीं लोगों को उस के लिए खड़ा करते हैं जो उन के अपने आदमी होते हैं। एम० पीज़० में 24 तेलंगाना क्षेत्र के होने चाहिए थे हमारे लोगों में से लेकिन केवल 12 ही हैं और राज्य सभा के अन्दर हमारी 8 सीट होनी चाहिए थी जिस में केवल एक सीट हमारी है। इस तरह इन में भी तमाम ऐसे हैं जो तेलंगाना को सपोर्ट नहीं करते हैं। सब इन्होंने अपने लोगों को रखा हुआ है। यह कहते हैं कि स्टूडेंट्स ने यह एजीटेशन किया है लेकिन उस में एम० ए०, बी० ए०, डाक्टर्स और इंजीनियर्स वह सब हैं, यह छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं। स्टूडेंट्स की हालत यह है कि उन्हें कालेजेज़ में प्रवेश मिलता नहीं और न मुलाज़मत मिलती है, वैसे तेलंगाना के लोग बड़े नम्र होते हैं लेकिन जब वह देखते हैं कि दूसरों को यह सब चीजें मिलती हैं और उन्हें कहीं जगह नहीं मिलती तो उन के अन्दर यह बगावत की भावना पैदा होती है। यह कुछ लोग बोलते हैं कि आन्दोलन हम लोग चला रहे हैं। मैं तो अपने लिए कहती हूं, शर्म की बात तो हमारे लिए है कि मैं पिछले अप्रैल 24 को जा कर इस में दाखिल हुई। इस के पहले तीन चार महीने तक मैं इस में शरीक नहीं हुई। अप्रैल के बाद मैं इस मूवमैंट में आई और मैं यह कहना चाहती हूं कि पुलिस के जुल्म से यह मूवमेंट बढ़ गया। सैकड़ों औरतों और मर्दों को जेल में बन्द कर के उन के साथ बड़ी बेरहमी का बर्ताव किया है। मुझे तो तेलंगाना समिति वालों ने विजिटर बना कर जेल में भेजा था, मैं, डा० मेलकोटे और बाकर अली मिर्जा साहब तीनों एक साथ वहां गए थे। मैं जेल की यह रिपोर्ट सभा-पटल पर रखना चाहती हूं। जेल के अन्दर कितने ही लोगों को मार डाला। उसे एक ग्रेवयार्ड बना दिया। हम को एतराज है सैंट्रल गवर्नमेंट से, चव्हाण साहब से मेरा एतराज है, चव्हाण साहब वहां गए थे तो वहां के चीफ मिनिस्टर ने उन से कहा था कि आप मदद दें तो मैं एक हफ्ते में इन को कंट्रोल करूंगा। लेकिन चार पांच महीने गुजर गए, कहां कंट्रोल कर पाए? सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में पुलिस वहां भेजी। आज वहां 20 हजार से कम पुलिस नहीं बैठी है। राजस्थान, मैसूर, यू० पी०, सी० पी० हर जगह से आपने वहां पर पुलिस को ला कर रखा है, जिन्होंने अकबजा बाजार, गोलगुडा, रहीमपुरा, धूलपेठ, गोल नाका, सब जगहों पर टैरर पैदा कर रखा है। हम एम० पीज़० वहां जा कर उन आदमियों के नाम नोट कर के लाये हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस को सभा के पटल पर रखना चाहती हूं। रात के समय ये सी० आर० पी० के लोग रेड करते हैं, सोये हुए लोगों को उठा-उठा कर ले जाते हैं, मारते हैं, इस तरह से जुल्म करते हैं। यह मूवमेन्ट इस तरह जुल्म करने से खत्म नहीं होगा। आज 30 लाख स्टूडेंट्स रोड्स पर पड़े हुए हैं, उन के साथ लेडी-स्टूडेंट्स भी हैं, कितनों को ले जा कर जेल में बन्द कर दिया है। यह पुलिस क्या करती है—सत्याग्रहियों को ले जा कर मारती है, अब जेलों में बन्द नहीं करते हैं, बुरी तरह से मार कर भेज देते हैं। अभी इसी महीने की 2 तारीख को श्रीमती वैंकटेश्वरराव का हाथ टूट गया, अभी हाल में 15 अगस्त को श्रीमती सुमित्रा देवी को जो एम० एल० ए० हैं, बुरी तरह से पीटा गया, पुरानी कांग्रेस की एम० एल० ए० को पीटा गया। हमारी इस मूवमेंट को इतनी ताकत पुलिस के जुल्म से मिली है। पुलिस

(श्रीमती लक्ष्मी बाई)

के साथ गुण्डों को भी बुला कर होटलों में रखा गया। अभी हाल में एक लड़का जिसका नाम कृष्णा था, जिसकी उम्र 25 साल की थी, जो तेलंगाना का था, बहुत पहलवान था, इन्जीनियर था, उस को गुण्डों के द्वारा मरवा दिया गया। जब उस की लाश को उठाया गया तो पुलिस ने फायरिंग किया और उस से 10-15 आदमियों की मृत्यु हो गई। वहां पर रात और दिन किसी समय चैन नहीं है। दिल्ली में तो फिर भी चैन मालूम होता है, लेकिन हैदराबाद में तो हर समय पुलिस का डर बना रहता है। ज़हीराबाद और संगारेड्डी की जेल में 300 लोगों के रखने की जगह है, लेकिन 2400 लोगों को रखा हुआ है, कबूतरखाने की तरह से लोगों को भरा हुआ है। अगर कोई कुछ कहता है तो उस की पिटाई की जाती है।

अभी हाल में—मिर्जा बाकर अली साहब, डा० मालकोटे और मैं, रहीमपुरा गये थे। वहां पर कर्फ्यू लगा था, घर से कोई बाहर नहीं निकल सकता था। उस दिन सवेरे एक घर में एक लड़का मर गया, पुलिस के डर से उसकी लाश को दफनाने नहीं ले जा सकते थे। साढ़े छः बजे शाम को हम लोग वहां पहुंचे और हम तीनों ने मिल कर लाश को दफन करवाया—इस तरह से वहां पर पुलिस टेरोराइज़ करती है।

आप कहते थे कि एक हफ्ते के अन्दर हम सब कन्ट्रोल कर लेंगे, लेकिन अब तक कन्ट्रोल नहीं कर सके। कांग्रेस प्रेसिडेन्ट वहां बातचीत करने के लिये गये। जब मैं और डा० मालकोटे जनता के प्रतिनिधि के रूप में उन से मिलने के लिए गये, हम को उसी दिन रास्ते में ही अरैस्ट कर लिया गया। अब ऐसी हालत में आप बताइये किस मुंह से हम कहें कि हम को सेप्रेट तेलंगाना नहीं चाहिये। हम हर तरह से—फाइनेन्शली, पोलिटीकली, बैकवर्ड हैं, हमारे इलाके का कोई डेवेलैपमेंट नहीं हुआ। ऐसा मत सोचिये कि सिर्फ तेलंगाना के लोग ही ऐसा चाहते हैं—आन्ध्र के लोग जो नौकरी के लिये तेलंगाना में जा कर बस गये, आज उन के बच्चे अपने आपको तेलंगाना का कहते हैं और कहते हैं कि हम को इस सरकार से दुश्मनी है, यह सरकार हटनी चाहिये। शुक्ला जी को मालूम होना चाहिए कि इस महीने वहां पर मिनिस्ट्री का जो एक्सपैंशन हुआ है, उस में ऐसे लोगों को लिया गया है, जो हालांकि तेलंगाना के हैं, लेकिन खुशामदी लोग हैं, जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उन के आने के बाद भी वहां पर 6 आदमियों को मार डाला गया। आप कब तक मारते रहेंगे और लोगों का खून बहाते रहेंगे।... (**व्यवधान**)... मेरा निवेदन है कि श्री नारायण रेड्डी जो अमेन्डमेन्ट लाये हैं उसको कबूल करना चाहिए।

अभी कोई भाई उधर से बोल रहे थे कि आंध्र के लोगों को खतरा है, उनको लूट लिया गया है, यह बिल्कुल गलत बात है। मैं कहती हूं कि एम० पीज० स्वयं यहां से जाकर वहां देख सकते हैं कि गलती किसकी है। कुछ लोग रांग रिपोर्ट देते हैं और बहकाने का प्रयत्न करते हैं। अगर ऐसी कोई बात हो तो जो भी चाहेंगे उसको भुगतने के लिए हम तैयार हैं। .... (**व्यवधान**).... यह क्या बात है कि हम को बोलने के लिए टाइम भी नहीं मिलता है। हमको बोलने के लिए अधिक टाइम मिलना चाहिए—चार पांच घंटे मिलने चाहिएं। वहां पर सैकड़ों लोग मर गए हैं, मैं एक औरत होने के नाते वहां की खराब हालत को यहां पर बयान करना चाहती हूं। वहां पर बच्चों का खून बहाया गया है, औरतों का खून बहाया गया है। 240 बच्चों को मार डाला गया—आखिर यह क्या बात है? बच्चों के मरने पर कितना दुख होता है? तेलंगाना के लोग इस बात का जवाब आपसे लेंगे।

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara): Mr. Speaker, Sir not only

has the Government of India failed miserably to tackle the situation that developed in Telengana but after hearing the stories especially these told by Dr. Melkote I begin to feel that we cannot merely in this country charge the Naxalites or the CPI (Marxists) for subverting democracy but the way these people have tackled this problem I have begun to feel, that they are subverting democracy in this country. After all, what has been described here is shocking. I want the Home Minister when he replies, to say what Dr. Melkote has described is not correct or not true. I think, Sir, even Jallianwala Bagh pales into insignificance compared to what has happened in this part of our country. And even after all that has happened this Government here sits silent with eyes open but mind closed. They don't want to admit that a situation has developed in a part of the country where practically no Government exists.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

मेरा कहना यह है कि ला ऐन्ड आर्डर सिचुएशन को जलियांवाला बाग से कम्पेयर करना उचित नहीं होगा । · · · (**व्यवधान**) · ·

अध्यक्ष महोदय: आप तो शांत मेम्बरों में से हैं ।

SHRIMATI LAKSHMIKANTHAMMA: You cannot incite the persons and then come and say here, Jallianwala Bagh. You are responsible for it.

अध्यक्ष महोदय: देखिये आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए ।

SHRIMATI LAKSHMIKANTHAMMA: Who asked innocent children to go on burning property with petrol ? (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: Do no quarrel with the gentle lady.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY: I think the tragedy is much more serious than Jallianwala Bagh in the sense that while Jallianwalla Bagh was a closed area and the shooting took place only one day, here in the open in nine districts for days together for months together this has been going on.

SHRI RANGA: I agree with the hon. lady that this is a wrong description of what has happened.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY: I have my view and I am not guided by Prof. Ranga.

SHRI RANGA: Yes, but he cannot go on exaggerating things.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY: I do not mince matters. I do not equivocate.

SHRIMATI LAKSHMIKANTHAMMA: In every State there are Jallianwala Baghs. in Bombay, there are.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY: Here is a case where the administration has been paralysed, the entire population is emotionally worked up. It cannot be said that this movement is a movement of urchins. When it has been going on for eight or nine months, can anybody say that this is not a popular movement, that it is not a mass movement? It is a mass movement —there is no doubt about it. How do you tackle such a mass movement? That is the question.

I would agree with the Government if they categorically adopt a policy of no further division of the country. But they should follow certain principles and policies. In this connection, I will be one with them if they say that we cannot divide the country on the basis of regional imbalance or economic backwardness. If a separate Telengana is advocated on the ground that it is regionally imbalanced or economically backward, I would not support it.

But here is a question which must be tackled. It is that the people there have completely lost faith in the present State administration. This has been proved beyond doubt. When the Chief Minister submitted his resignation, what did he himself say? 'I am not able to tackle the situation'. If the Government of India had any love for democracy, they would not have left this matter as a party matter concerning the Congress Party only, the Congress legislators

[Shri Surendranath Dwivedy]

of the State only to decide whether they had confidence in him or not, or they wanted him to continue or not. The only course left for the Government, since there was no law and order in that part of the country, was to invoke President's rule. That should have been done much earlier in order to avoid all those atrcities of which we heard today.

The troubles we have faced or are going to face in future on this score are because the Government of India did not listen to the advice of the SRC. SRC was constituted because of the agitation of different linguistic groups in the country to have separate States for themselves. They did not abide fully by the recommendations of the SRC. When the recommendations were published, at that time Pandit Nehru was there, we found there were some remarks against UP. Pandit Nehru himself expressed surprise. As you know, the Commission was composed of eminent men in our public life, men of integrity and a judicial bent of mind, Pandit Kunzru, Justice Fazl Ali and Sardar Panikkar. Government sat in judgement over the recommendations of the Commission So far as Telengana was concerned, they had made some recommendations. When Vishal Andhra was formed, did they fully accept those recommendations? They have clearly stated :

> "Integration of Telengana with Andhra at this stage is, therefore, likely to create administrative difficulties both for Andhra and Telengana."

They say 'at this stage'; they were not opposed to integration. Those were prophetic words. They suggested two courses. They did not categorically say what you are visualising now. That is, the so-called gentleman's agreement. Somebody was joking: how can you have gentleman's agreement when a lady is the Prime Minister; What value has that ? Whatever it is, the so-called aentleman's agreement was never implemented. It is agreed on all hands that there has been injustice. They say :

> "It seems to us that neither guarantees on the lines of Shri Baug Pact nor constitutional devices such as 'Scottish Devolution' in the United Kingdom, will prove workable or meet the requirements of Telengana during the period of transition. Anything short of supervision by the Central Government over the measures intended to meet the special needs of Telengana will be found ineffective."

When the gentleman's agreement was there, if there was this statutory obligation on the part of the Central Government, probably things would have been better. They did not do anything like that.

Now it is wrong to speak as if the Telengana Telenganites are the enemies of Andhra or *vice versa* it is wrong to speak as if they are already two separate independent countries. The SRC said in the interest of the entire Andhra region for the time being let us have a separate State called Hyderabad State. But that recommendation was not accepted and what they feared has come true. Now there seems to be no confidence among the people of Telengana; they do not seem to have confidence in the present administration that they would get a fair deal. The Government there has failed . This Government has also failed because of party and group interests. They did not want to disturb Brahmananda Reddy lest his support may go to this group or that group. They are fighting among themselves and the country is suffering. Even at this late stage, my request to them is to consider this matter dispassionately. I do not think that by having a person from Telengana as Chief Minister in the present set of administration you are going to solve the problem; it will be a smoke screen. The problem today is one of creating confidence in the minds of the people of Telengana so that they can have a feeling that in any future administration they will have a better deal. My specific proposals in that direction are: all prisoners be released; let normalcy be restored. If the Government has failed and if they now find it difficult to proceed in the matter because of political or other considerations, let a parliamentary committee go there. And I am sure that committee will have the picture of the entire country in their view as also considerations of national integration and let them find out facts and judge whether at this stage of our national progress we should create another small state or not. Let them meet

people and discuss things with them. I suggest to the Government to accept this amendment so that a parliamentary Committee could go there. Parliament is above any Government, State or Centre and so let them also give this assurance. Let them accept this: and whatever recommendations are made by the Parliamentary Committee will be acceptable to the Government and to the Andhra Government also.

MR. SPEAKER: Before I call upon Shri M.V. Krishnappa, I would invite your attention to a change in the allotment of time tomorrow. The Home Minister is going out for a couple of days and therefore I propose that this debate be continued on the 21st, because without him, I do not think it would be worth-while to continue with this debate during his absence.

SOME HON. MEMBERS: Agreed.

MR. SPEAKER: Then, the half-hour discussion is in the name of Shri Tapuriah. I do not find him sitting here. If he is not there, we can utilise that half an hour for this debate also. We will wait till he comes, but if he does not come, this half-an-hour that is available to us will be given to this debate.

SHRI M. N. REDDY: On the 21st, will this at 3 O'clock ?

MR. SPEAKER: At three or half-past three; it will be to your convenience. Now Mr. Krishnappa.

SHRI M.V. KRISHNAPPA (Hoskote): If the hon. Member comes, I will be in possession of the House and I would continue on the 21st.

MR. SPEAKER: Let him finish today, of course. If Mr. Tapuriah does not come, we shall continue the debate.

SHRI M.V. KRISHNAPPA: If he comes, I will be in possession of the House. Sir, I find from the speeches of all the hon. Members who spoke, both from Andhra and Telengana, that they are unanimously of the opinion that both in the interests of Andhra and Telengana, they should part like friends. Prof. Ranga is not a Member of today: he is there since the last 50 years, serving Andhra. Dr. Melkote from Telengana is one of the ablest labour leaders of this country, and the other Members who spoke on either side have given a vivid picture of the things that are happening there.

As is said, that confidence which the people of Telengana should have in the Government of Andhra Pradesh has completely gone. When that is the case, I do not know why all the people are wanting that they should separate like friends. The Government should not agree to it. There is a proverb in Kannada which means that even though the complainant is prepared to withdraw the case, the witness is not prepared to withdraw it. So, here, the witness is objecting to the withdrawal. Government of course have their own problems. But how long can they resist this movement, when the entire population wants it ? The future generation, the students, are determined that they have no future in Telengana unless they separate themselves from Andhra Pradesh When they have decided like that, and when they are all agitating for the last seven or eight months in the country, the Government cannot stop it there, and they cannot go on killing people. As Shri Surendranath Dwivedy said, they should have said earlier, "No division of the country." You said it long ago. We opposed it 17 years ago. In the same month of August, a resolution was moved. In August 1952 it was moved. A resolution for the formation of linguistic States was moved. I was a Member and opposed it. Not that I was in the Opposition then; but the Congress Members were in such a strength that I was sitting there in a corner. But unfortunately, immediately after my speech, I was appointed as a Minister.

AN HON. MEMBER: Why unfortunately ?

SHRI M.V. KRISHNAPPA: And then the linguistic States came. All that is happening today, we had forethought then. We said that if the country was divided, on linguistic grounds there is going to be linguistic fanaticism and there is going to be opposition to Hindi; and there is going to be all the trouble that we are seeing today because of the linguistic division of the country. Anyway, the linguistic States came into being. In

[Shri M.V. Krishnappa]

Andhra Pradesh, Potti Sriramulu starved and died in Bezwada, and the Andhras got a linguistic State. And other linguistic states came in. Nehru was dead opposed to it. All the people were opposed to it. But it came about.

Now, what is the condition in Telengana ? Four days back I was travelling in Telengana incognito. In the train I met one of my old colleagues, an inspector of police, at Tadepallegudam station. When I enquired him what he was doing there he told me "an Andhra Minister is travelling in the next compartment; I am watching him along with eight police constables". He added that he has to watch the movements of not only Ministers but also dacoits. It seems that the dacoits are taking advantage of the Telengana situation and there is a fear of their attacking the Ministers. Imagine a situation where the policemen have to watch both Minister and dacoits?

When Shri Brahmananda Reddi came to Bangalore to attend the Congress Session the Mysore Government posted eight sub-inspectors, two inspectors and 72 constables to protect him. The other day when I passed through Hyderabad airport I found that nearly 1,000 policemen were protecting Shri Brahmananda Reddi in his own home State. Who is in jail—Shri Chenna Reddi or Shri Brahmananda Reddi? If Shri Brahmananda Reddi had to be surrounded by thousand policemen in his own State of Andhra, why should he keep Shri Chenna Reddi in jail? When about ten peoples are protecting Shri Chenna Reddi, hundreds or thousand policemen are protecting Shri Brahmananda Reddi, the Chief Minister of a State, who is expected to be loved and respected by the people of that State.

Why should we condemn this demand for a separate Telengana State ? Our Home Minister might say that if we concede this demand then there will be demand from other areas for separate States. In that case, appoint a Commission on the lines of the States Reorganisation Commission. After all, you cannot brush aside such a demand. You said "no Punjabi Suba" then you gave it. So, why not give Telengana people what they want? Do you want to kill some more people before you grant a separate State? Because, I am sure you are going to give it, as you did in the case of Haryana and Nagaland. Perhaps, you will kill some more people and then give Telengana.

Then we are going to start an agitation for old Mysore State and certainly we will never stop until we get it. Because, exploitation is going on in that area in a much greater degree than in Telengana. Mysore is like an elephant. It takes a little time for the elephant to get up. You must push it and kick it. But once it gets up you cannot stop it. Mysore is going to get up like an elephant. The younger generation are preparing the ground for it. Just as the people in Telengana see no future, in Mysore also the younger generation see no future because of exploitation. Students in the universities of Mysore feel that they have no future in that State unless they belong to a particular caste. Unless they belong to that caste, they cannot become a Chief Engineer or the head of a Department So, yesterday 1,400 students have observed a token strike. Perhaps, because of the Presidential elections it was not given very much publicity in Delhi. The local press has given wide publicity to it. The people of Mysore are preparing their case on economic and political grounds for their legitimate demands. When a demand is backed by a large section of the population and it is genuine, the people in charge of administration must give serious thought to it, as Shri Venkataswamy said a short while ago.

I have great respect for Shri Chavan, the Home Minister. We were colleagues in the fight for the freedom of the country. He was one of the revolutionaries at that time. Then we were called goondas and rowdies by the British. We are using the same expressions against the people of Telengana, which is wrong. They are patriots. The movement in Telengana is spontaneous and it is high time that government appointed a commission to go into the entire question. If your argument is that the States cannot be divided into smaller units, remember that even a person of stature of Sarvodaya leader Jaiprakash Narain has advocated smaller States in India with a strong centre. I think it is

high time for the government to think on those lines. Let us have more states like United States of America. If you can allow Goa exist separately as a viable independent unit, if you can allow Pondicherry to exist as a small State, why can't you allow the same privilege to Mysore, with a population of one and a half crores, or Telengana with a population of one and a half crores, or Vidarbh or Saurashtra?

How long will Chavan, Morarji Desai and Nijalingappa be living in this country? We should not take these things on the personal level. There are people; there are the generations. How long will you be living and how long will you be in power?

If you agree for Telengana, Old Mysore people will be demanding Old Mysore; Vidarbha people will be demanding Vidarbha and Saurashtra people will be demanding A Saurashtra and we will be no more. But he has so many other problems. So, you tell us that the country has to face so many other problems. We can postpone it for some time. The Government of India always does postpone things by appointing a committee. Appointing a committee means postponing an issue. You do it now. You appoint a committee on the SRC model. Have some experts and judicial people. You are not the judges now; you are a party in the struggle now. You are killing them. You are butchering democracy in Andhra, as Shri Dwivedy said. It can be compared with the Jallianwala Bagh. Jallianwala Bagh was closed thing; here it was an open area. Hundreds and thousands of people had taken part and they were beaten and wounded. That is the case. In a free country like India these things should not continue, whatever be considerations.

I had some facts and figures but I have to leave these to friends from Telengana to place because unless they speak here, tomorrow if they go back they will be beaten by their own people. I request you on behalf of them that all the Members from Telengana should be given some chance so that tomorrow when they go back they can show their faces to the people. I request Shri Chavan to accept a commission to go into the matter or, as Shri Dwivedy suggested, an impartial committee of Parliament Members should go and study things and report to Parliament.

MR. SPEAKER: Shri Joshi.

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH): Sir, I take it that the half-an-hour discussion will not be taken up today.

MR. SPEAKER: That was in the name of Shri Tapuriah. He is not here. So, because they wanted more time, I have given this half an hour to them. They can avail of it today.

श्री एस० एम० जोशी (पूना): अध्यक्ष महोदय, यह एक दुर्भाग्य की बात है कि आज हम लोगों को इस वातावरण में तेलंगाना की प्रजा की शिकायत रखनी पड़ रही है। मैंने कुछ दिन पहले वहां जा कर देखा था और यहां एक बिल आया था उस वक्त भी मैंने अपनी भावना लोगों को बताई थी। आज मुझे दुख इसलिए है कि उन लोगों को अपनी सुनवाई करवाने के लिए 250 से ऊपर जानें कुर्बान करनी पड़ी हैं। जब हम लोग कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के माने तो मैं यह समझता हूं कि किसी भी सवाल के लिए कोई झगड़ा हो तो वह झगड़ा हम लोग आपस में बैठ कर विचार विमर्श कर के तय करें। अगर हमारे इस लोकतंत्र में लोगों को इतनी कुर्बानी देने पर उनकी सुनवाई हो तो मैं नहीं समझ सकता हूं कि हमारा लोकतंत्र कितना कारगर हो रहा है। कहा जाता है कि यह तो एक बच्चों का आन्दोलन है। हो सकता है। मैं जब 14-15 मार्च को वहां गया था और अपने मित्रों से मैंने यह पूछा कि क्या यह आन्दोलन बहुत दिन तक चलने वाला है? तब उस वक्त तो वह जवाब नहीं दे सके। मगर उन में से कई लोगों ने कहा था कि यह आन्दोलन बहुत देर तक चलने वाला है क्योंकि यह आन्दोलन जनता का है, उस का कोई नेता नहीं है। किसी पार्टी ने उस का

[श्री एस० एम० जोशी]

समर्थन नहीं किया है । यह तो सरकारी नौकरों ने शुरू किया उन के ऊपर जो ज्यादती हो रही थी, जो नवजवान थे जिन की रोजी छीन रहे थे, उन लोगों ने शुरू किया और बाद में ये सब नेता लोग आये हैं । कई लोग यह कहते हैं कि जो डिस्ग्रन्टल्ड पोलिटीशियन्ज़ हैं, उन्होंने वहां जाकर इस को शुरू किया । मुझे याद आता है, जब हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ते थे, तब कहा करते थे कि हिन्दू और मुसलमानों में ब्रिटिश लोग झगड़ा कराते हैं, लेकिन इस की जड़ में कोई चीज़ होगी, तभी तो ये झगड़े चलते हैं । यह जड़ क्या है, यह हम लोग नहीं देखते हैं ।

दूसरी बात---मैं यह देखता हूं कि जखम पर नमक छिड़कने की कोशिश की जाती है । कोई यदि संविधान में रह कर अपने हक़ की मांग करता है, तो वह विघटनकारी कैसे होता है, इस में क्या विघटनकारी है । अगर वह नेशनल इन्टीग्रेशन के खिलाफ़ है, डिसइन्टी-ग्रेशन है, तो नेशनल इन्टीग्रेशन की जो कौन्सिल है, क्या उन लोगों ने कभी इस प्राबलम को हल करने की कोशिश की ? मैं तो समझता था कि जब नेशनल इन्टीग्रेशन की कोई स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है तो उस का फर्ज था कि इस पर विचार करती, इस पर एमरजेंट मीटिंग बुला कर चर्चा करनी चाहिये थी । लेकिन कुछ नहीं हुआ । बाद में जब यहां पर चर्चा हुई तो हुकूमत ने बड़े दबाव के बाद यह माना कि अगर कोई पार्लियामेन्ट्री कमेटी जाती है, तो हमारी तरफ़ से कोई आपत्ति नहीं है लेकिन वहां के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यह तो सेन्टर का इन्टरफीयरेंस हो जायगा, हम पार्लियामेन्ट के इन्टरफीयरेंस को कबूल नहीं करेंगे, अगर कोई सर्वदलीय पार्लियामेन्ट्री कमेटी वहां जाती है और वे लोग कोई तसल्ली देने की कोशिश करते हैं तो यह कहा जाता है कि यह हमारे मामले में इन्टरफीयरेंस है, हम उस को कुबूल नहीं करेंगे । उस के बाद लड़ाई झगड़े चले, इतनी कुर्बानियां हुई और फिर वहां के चीफ मिनिस्टर साहब ने इस्तीफा दे दिया ।

अध्यक्ष महोदय, उसी दिन साढ़े ग्यारह बजे रात को **इण्डियन एक्सप्रेस** के प्रतिनिधि ने मुझ से पूछा कि इसके बारे में आपको क्या कहना है । मैंने कहा---मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं । उन्होंने बताया कि दूसरे लोगों ने तो बड़ा वैलकम किया है । मैंने कहा---होगा, लेकिन इन्होंने इस्तीफ़ा अपने पार्लियामेन्ट्री बोर्ड को दिया है, इस का कोई नतीजा निकलेगा, ऐसा मुझे तो नहीं लगता है । फिर भी लोगों ने वैलकम किया है, तो ठीक है । लेकिन मेरी यह मजेश्चन थी---इन्होंने इस्तीफा दिया है, अच्छी बात है, लेकिन इस के साथ-साथ सभी प्रिज़नर्स को भी छोड़ दिया जाय ।

एक सदस्य ने यहां पर एक दफ़ा ज़िक्र किया था---यह उस समय की बात है जब प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट आपने बनाया था---कि पोलिटीकल मामलों को लेकर इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिये, आपने वायदा भी किया था, लेकिन 280 लोग वहां पर कई महीनों से प्रीवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट में बन्द पड़े हैं । हम लोग क्या कर रहे हैं । हमारे मित्र जार्ज फरनेन्डीज़ ने जब शिव सेना का झगड़ा हुआ था, तब बालठाकरे की रिहाई की भी मांग की थी । मैंने कहा कि कैसे कर देंगे । उन्होंने कहा कि प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट में नहीं पकड़ा जाना चाहिये । हम नहीं चाहते कि किसी को प्रीवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट में पकड़ा जाय, तीन-तीन महीने तक बिना किसी सुनवाई के बन्द रखा जाय, यह मुनासिब नहीं है, इस की कोई हद होनी चाहिये । उन लोगों को यह कहा जाय कि तुम्हारी विघटनकारी शक्ति है, यह ठीक नहीं लगता है ।

अब ऐसी हालत में क्या करना चाहिये ? मेरे मित्र ने जब कहा कि हम तो सेप्रेट तेलंगाना चाहते हैं तो मैंने कहा---देखो, भाई, आन्ध्र के भाई, तुम लोगों ने जब खुद अपना एक आन्ध्र

स्टेट बनाया, से सिलसिला शुरू हुआ, वह अभी खत्म नहीं हो पाया है कि तुम्हारा दूसरा सिलसिला शुरू हो गया, इस तरह से कैसे काम चलेगा, हम को सोचना चाहिये तब मुझ से पूछा गया कि विदर्भ के बारे में आप क्या करेंगे ? मैंने कहा कि मैं महाराष्ट्र से आता हूं और मैं तो यही चाहता हूं कि सब महाराष्ट्री एक साथ रहें। निजलिंगप्पा और दूसरे लोग कहते हैं कि आंध्र विधान सभा में तेलंगाना की मेजारिटी नहीं है। वह उनकी स्थिति है लेकिन क्या अगर मेजारिटी नहीं है इसलिए उनको न्याय नहीं मिलेगा ? जहां तक विदर्भ के लोगों की भावना को हम लोग समझते हैं, वे लोग ऐसी मांग नहीं करेंगे। अगर उन्होंने मांग की, जिस तरह से तेलंगाना के लोगों के साथ बर्ताव होता है वैसे ही महाराष्ट्र के लोग भी करेंगे तो फिर मैं कहूंगा कि विदर्भ को भी मानना पड़ेगा।

श्री योगेन्द्र शर्मा : विदर्भ का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तो तैयार थे।

श्री एस० एम० जोशी : चीफ मिनिस्टर बनाने से क्या होता है। जब चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया तो बनाने के लिए तैयार थे....

श्री एम० नारायण रेड्डी : सही इस्तीफा नहीं था इसलिए कोई बनाने के लिए तैयार नहीं था।

श्री एस० एम० जोशी : तो मैं उस चीज को ज्यादा दोहराना नहीं चाहता हूं। यहां पर होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, जब आसाम का बिल चल रहा था तो मैंने कहा था कि एक अमेन्डमेन्ट दे रहा हूं, सिर्फ आंध्र के लिए देता हूं, उनको राजी करने के लिए। आसाम के लिए हमने जिस तरह की आटोनामी दी, वैसी ही इन लोगों की मांग आ जायेगी तो उसको भी कबूल करेंगे—ऐसा अमेन्डमेन्ट मैंने रखा था। उस वक्त होम मिनिस्टर ने कहा टैक्निकली तो यह चीज चलेगी नहीं क्योंकि खारिज हो जायेगी। लेकिन टैक्निकली जो कारण है उस पर स्टैंड नहीं लेते हैं, पोलिटिकली उसको रेजैक्ट करते हैं, मैं कहता हूं कि एक समय था जब हमको बार-बार कहा जाता था कि ला ऐन्ड आर्डर का सवाल है, फिर ला ऐन्ड आर्डर का सवाल एक रात में पोलिटिकल सवाल कैसे बन गया ? उस वक्त जब पोलिटिकल सवाल हुआ तो ला ऐन्ड आर्डर का अब कैसे हो सकता है ? प्रधान मन्त्री को अफगानिस्तान न जाना था लेकिन रात को वे वहां चली गई, गृह मन्त्री जी भी चले गए, इसलिए मैं समझता हूं वह पोलिटिकल सवाल हुआ। अब पोलिटिकल सवाल का पोलिटिकल हल भी निकालना चाहिए। मेरी मांग है तेलंगाना के लोगों को राजी करो। तेलंगाना के लोग एक आंध्र में रहने के लिए तैयार हैं तो ठीक है। अगर सिर्फ डिवोल्यूशन आफ पावर से राजी होते हैं तो ठीक है, आटोनामी से उन्हें संतोष है तो ठीक है मुझे कोई उज्र नहीं है परन्तु सरकार इसी तरह से काम चलायेगी तो इनकी डिमांड इरेसिस्टेबिल हो जायेगी। और इस अन्याय को हम कभी बर्दाशत नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरी नम्र प्रार्थना है कि इस मामले को ज्यादा देर तक नहीं चलाना चाहिए, जल्दी-से-जल्दी कोई हल निकालना चाहिए। मैं इस चीज को सही मानों में कबूल नहीं करता कि वहां कमेटी जाये लेकिन अगर वहां के लोगों की राय है और वहां कोई पार्लमेन्ट की कमेटी जाती है उससे उनको तसल्ली होगी तो उसमें भी हमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन कोई कमेटी जायेगी वह कारगर तभी हो सकती है जब वहां के लोगों को जो बन्द किये गए हैं, दो-दो महीने हो गए हैं नेताओं को प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट में बन्द कर रखा है, उनको छोड़ देना चाहिए और उनके साथ बात करनी चाहिए। इसके साथ-साथ उन लोगों को एक आश्वासन यह भी मिलना चाहिए कि जो सर्वदलीय कमेटी वहां जायेगी अध्ययन करने के बाद जो वह सिफारिशें

[श्री एस० एम० जोशी]

करेगी उनको हुकूमत मान लेगी । ऐसा आश्वासन हो तो मैं समझता हूं तेलंगाना के लोग राजी हो सकते हैं। ऐसा कोई हल निकालेंगे तो अच्छा होगा। आज देश की स्थिति बहुत गम्भीर है लेकिन साथ-साथ इस परिस्थिति को भी कैसे आगे बढ़ा सकते हैं ? बहनजी अभी जो कह रही थीं वह कितने उमंग से कह रही थीं, उनको आप रोक नहीं सके । उनमें एक अन्दरूनी उभार आ रहा था जिसको वह रोक नहीं सकीं । इन चीजों को देखते हुए मैं समझता हूं श्री नारायण रेड्डी का जो सुझाव है उसको मानें, श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी जो उस वक्त इस्तीफा देने के लिए तैयार थे वह ले लें और जो कुछ करना है करें या फिर कम-से-कम इस के ऊपर राजी करें । अगर आप कहें कि इन्टरफियरेंस वाली बात नहीं मानते हैं, इंटिग्रेशन वाली बात मानते हैं तो पार्लमेन्ट कमेटी की बात मान लेनी चाहिए । नहीं तो यह कहां का इंटिग्रेशन है। इसलिये उनको राजी करना चाहिये और राजी करने के बाद कमीशन वहां जाय तो मैं समझता हूं कि उन लोगों को वहां तसल्ली होगी और कोई रास्ता निकल आयेगा । यही मुझे कहना है ।

श्री गंगा रेड्डी (आदिलाबाद) : जनाब सदर महोदय, मैं तहे दिल से मशकूर हूं कि आप ने मुझे यह मौका इनायत किया । यह मसला डेढ़ करोड़ तेलंगाना में रहने वाले इन्सानों का है। 8 महीनों से जहां आम जिन्दगी मुअत्तल हो चुकी है, पूरे मदरसे बन्द हैं, 16 लाख बच्चे एक साल गवां चुके हैं और दूसरे साल के दो महीने गवां चुके हैं और इस प्रोबलम का कोई हल अभी नजर नहीं आता। जहां अब तक 200 से अधिक लोग गोली का निशाना बने, 50,000 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया, और बहुतों को पी० डी० ऐक्ट में गिरफ्तार किया गया और राजमुंधरी जेल में रखा गयां लीडरों को । आज हर बच्चे की ज़बान पर यह है कि तेलंगाना अलग बने । क्या इन की यह कुरबानी बेकार जायगी, क्या इन्सान का खून पानी से सस्ता हो गया है ? मैं यकीन के साथ कहूंगा कि यह कुरबानी बेकार नहीं जायेगी, खून अपना रंग जरूर लायेगा ।

तेलंगाना में जो जुल्म, ज्यादती हुई है उसका कहना मुश्किल है । उन माओं से पूछिये जिन के बच्चे मारे गये । उस बीबी से पूछिये जिस की मांग का सिंदूर मिटा। उस बाप से पूछिये जिस के आंखों का नूर और बुढ़ापे का सहारा छूटा । उन यतीम बच्चों से पूछिये जिन के बाप मारे गये । जब इतना भयानक मामला नज़रों से गुजरता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और शर्म से आंखें झुक जाती हैं । हमारे धर्म में कहा गया है कि बाप के किये हुए पाप का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है, हुकूमत की की हुई गलती की सत्ता अवाम को भुगतनी पड़ती है। यही वजह है कि रियासते आंध्र प्रदेश, जो एक सरसब्ज और शादाब रही है, मुसलमल सूखे और बाढ़ का शिकार बनी हुई है ।

फ़जल अली कमीशन ने साफ अल्फाज में कह दिया था कि हैदराबाद को अलग स्टेट रखा जाय । मगर दोनों पंडितों ने, पंडित नेहरू और पंडित पंत ने तेलंगाना और आन्ध्र की खिलाफ़ मर्जी के दोनों की शादी करा दी । नतीजा यह हुआ कि तलाक की नौबत पैदा हो गयी है । मैं आप से कहूंगा कि एक जैन्टिलमेंट एग्रीमेंट बनाया गया था, उस का अगर सही तरीके से उर्दू में तर्जुमा करूं तो शरीफ़ों के दर्मियान एक मुआहिदा है । तो दोनों शरीफ़ हैं या नहीं यह इससे पता चलेगा कि हम हर मामले में, मुलाज़मत, उखमत और तरक्की के मामले में नाइंसाफी की गयी है । यहां तक कि तेलंगाना रीजनल कान्सिल को कमेटी में तबदील कर दिया । और यहां तक कि आर्गेनाइज़ेशन लेबिल में तेलंगाना प्रदेश कमेटी को 1962 तक बरकरार रखने के बजाय आंध्र प्रदेश में जा कर

दिया। शुरू से ही डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर का औहदा बर्खास्त कर देना यह जाहिर करता है कि उन्होंने फ़ातिहाना तरीके पर काम किया है और 13 साल तक तेलंगाना वाले इस को बर्दाशत करते रहे। मैं कहूंगा कि तेलंगाना वाले कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि वे शरीफ़ हैं। शराफ़त का बेजा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तेलंगाना वाले हक के लिये लड़ रहे हैं। भगवत् गीता में कहा गया है कि हक के लिये लड़ना धर्म है। अगर हक के लिये न लड़ा जाय तो बुजदिली है।

पुलिस की ज्यादतियों का जिक्र दूसरों ने किया है कि बगैर नम्बर प्लेट के गाड़ियों में और बगैर ड्रैस के जा कर क्या-क्या जुल्म करते हैं। कहा जाता है कि गुंडे भी पुलिस के दल में शरीक हो कर लूट मार करते हैं। अक्सर लोगों ने कहा कि तेलंगाना वालों ने आंध्रावालों पर बहुत ही जुल्म किये मगर किसी अखबार में यह नहीं आया कि किसी को मारा गया, किसी की अस्मत लूटी गयी। अगर ऐसा है तो मेरी एक मांग है कि होम मिनिस्टर साहब एक कमेटी मुकर्रर करें और जांच करायें कि कितनों के साथ जुल्म या ज़बरदस्ती की गयी ताकि जो गलत किस्म की अफ़वाहें हैं वे जल्दी दूर हों।

मुशीराबाद जेल में मुल्जिमों ने किस बेरहमी से सत्याग्रहियों को पीटा वह अखबार में शाया हुआ था और जेलों में पुलिस का जो लाठी चार्ज हुआ और उस से भी सब वाकिफ़ हैं। एक चीज़ और आपके सामने रखना चाहता हूं।—

तेलंगाना के किसी जेल में जगह नहीं है। मदरसों को जेलों में तब्दील कर दिया गया। मेरे जिले में इन्डस्ट्रियल एस्टेटों को, जो अभी शुरू भी नहीं हुई थीं, जेलखाना बना दिया गया। आज ला ऐंड आर्डर बाकी नहीं है। वहां के नुमाइन्दों का आवाम से क्या ताल्लुक है यह आप खुद जानते हैं। अगर हमारे दस्तूर में रिकाल का प्रावीजन होता आज हम यहां नहीं होते। आज हम लोगों की कोई वुकत हमारी कांस्टिटुएन्सी में नहीं है। पूरी अवाम इस अवामी तहरीक में हिस्सा ले रही है और हम सब उन से कट चुके हैं। एन० जी० ओज़० की 35 रोज हड़ताल वहां चली। 35 रोज तक दफ्तर बन्द रहे। दफ्तर तो बन्द नहीं रहे लेकिन वहां कारोबार नहीं हुआ। अगर पेट की मजबूरी न होती तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि दफ्तर कभी न चलते। चूंकि पेट की मजबूरी थी, बीबी-बच्चों की आहें वे देख नहीं सके लिहाजा मजबूरन हड़ताल बन्द कर के दफ्तर जाना पड़ा। वहां पर आठ महीने से प्राहिविटरी आर्डर है। कुछ दिन तक वहां कम्प्लीट कर्फ्यु रहा। उस से हैदराबाद और सिकन्द्राबाद में बेवगी का आलम था।

मैं कहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आठ नुकाती प्रोग्राम बनाया जो बिल्कुल गैर-तशफ्फीबख्श और नाकाम साबित हुआ। वहां जून में गैरदानिशमन्दाना तरीके पर पुलिस के जोर पर मदर्से खोल कर कोर्स कम्प्लीट न होने के बावजूद इम्तहान मुनक्किद करना चाहा, जिस का नतीजा क्या हुआ? बदअमनी फैली। बच्चों पर फायरिंग की गई जिस से 50 बच्चे मरे। इससे वहां की हालत साफ जाहिर होती है।

आन्ध्र प्रदेश में पूरे एलेक्शन मुल्तवी हो गये हैं। पंचायत एलेक्शन भी मुल्तवी कर दिये गये हैदराबाद म्यूनिसिपल कमेटी के एलेक्शन मुल्तवी कर दिये गये। वजह क्या है? अगर एलेक्शन मुनक्किद होते तो एक भी कांग्रेस का मेम्बर चुन कर नहीं आ सकता था। अभी हाल ही में मैंने अखबार में पढ़ा कि हैदराबाद सब-कमेटी के एलेक्शन हुए जिस में सेपरेट तेलंगाना का नारा लगाने वालों ने पूरी सीट्स कैप्चर कर लीं। इस से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि यह कितना अवामी मूवमेंट है। हैदराबाद में एम० एल० सीज० का एलेक्शन हुआ। उस में प्रजा

समिति के सेक्रेटरी वेंकट रामा रेड्डी चुन कर आये । हालांकि पैसे की ताकत पर सरकारी कैन्डीडेट को बैक किया गया फिर भी वेंकट रामा रेड्डी चुन कर आये । यह खुद सबूत है कि तेलंगाना का आन्दोलन किस हद तक मजबूत हो चुका है ।

बदअमनी की हालत यह है कि जो वजरा इस्तीफा दे चुके हैं उन्होंने एक जबान हो कर मांग की थी कि यहां पर प्रेजिडेंट्स राज इम्पोज किया जाये क्योंकि यहां पर अमन व अमान बरकरार नहीं है । प्राइम मिनिस्टर का एयर डैश, रातो रात आ कर वापस चले जाना और उस के बाद श्री चव्हाण की आमद, तीन दिन तक गुफ्तगू, इस सब से यकीन आया था कि यह मसला हल होगा और यह लोग दिलचस्पी ले रहे हैं । लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हालात ज्यों की त्यों हैं और कुछ नहीं हुआ । हुआ क्या ? काबीना का तौसी, यानी सयासी बेरोजगार लीडरों के लिए कुछ मुलाजमतें खुल गई और सरकारी मालियत पर कुछ भार पड़ा । लेकिन इस से मसला हल होने वाला नहीं है ।

चूंकि यह मसला मेरे इलाके का है, इस लिये मैं कुछ सजैशन्स रखना चाहूंगा । अगर तेलंगाना नहीं बना तो हम अपनी कांस्टिट्एन्सी में जा नहीं पायेंगे । ला ऐंड आर्डर की हालत यह है कि आज भी मिनिस्टर वहां खुले आम फिर नहीं सकते । अगर जायेंगे तो पुलिस की बन्दूकों और बर्छियों के बल पर । आप ने वजीर दाखिला का खम्मम का दौरा देखा होगा । उन के दौरे में सिर्फ चार जानें गई । अगर हर मिनिस्टर के दौरे में चार जानों के जाने की जरूरत पड़ती है तो मैं समझता हूं कि एक दिन आयेगा जब तेलंगाना के लाखों लोग गोलियों के निशाने बन जायेंगे ।

अगर हुकूमत को जम्हूरियत पर विश्वास है तो राय आम्मा मुकद्दम है और उन को राय आम्मा को सुनना पड़ेगा । आज सेंटर ने क्या किया ? हम ने मांगा पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, उन्होंने कहा नहीं, हम ने कहा कि सब-कमेटी दीजिये, उन्होंने कहा नहीं । जैसा गजेन्द्रगडकर कमेटी ने कहा उस को मौका दिया जाय, तेलंगाना की रीजनल कमेटी के अख्त्यारों में इजाफा किया जाये, तो कहा कि नहीं । मैं कहना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है कि हम इस पर अज सरे नौ गौर करें । जैसा मेरे दोस्त ने कहा, हम आइडियोलोजी की खातिर हजारों लोगों की जानें नहीं ले सकते, आइडियोलोजी की खातिर करोड़ों आदमियों को कुर्बान नहीं कर सकते । वक्त आ गया है कि हम अज सरे नौ इस पर सोचें कि तन्जीम जदीद किस तरह की जाय । इस के लिये एक एस० आर० सी० कमेटी बिठाइये । और उस की जो रिकमेन्डेशन आये हम उस पर सोचें कि इस के बारे में क्या तरमीमात की जायें । अगर एकसालमियत को उस से नुक्सान पहुंचता है, अगर छोटी रियास्तें बनने से मुल्क की एकसालमियत को खतरा होता है, तो मैं पूछूगा कि जब हरियाणा और नागालैंड बना था तब यह नारा किधर गया था ? उस वक्त यकसालमियत की बात नहीं कही गई । जब माफिक कोई चीज बैठती है उस वक्त तो वह ठीक होती है लेकिन जब कोई चीज सूट नहीं करती है तो आप यकसालमियत और दूसरी इस तरह की चीज बीच में लाते हैं । मैं कहूंगा कि अगर छोटे राज्य बनेंगे तो सेंटर मजबूत होगा । सेंटर को मजबूत होना भी चाहिये । जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उन में मजबूत सेंटर की जरूरत है । तेलंगाना आपने दिया तो सेंटर कमजोर नहीं होगा, बल्कि मजबूत होगा ।

18 hrs.

मैं कहता हूं कि आप ओपिनियन पोल वहां कराइये । अगर ओपिनियन पोल करवाना है तो जो वहां इस वक्त हकूमत है उसका

बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, इसलिए वहां आप तीन महीने के लिए प्रैजीडेंट्स रूल इम्पोज़ करें और इस बीच में ओपिनियन पोल करवायें आप लोगों की राय जानिये और यह तभी जानी जा सकती है जब वहां प्रेजीडेंट्स रूल इम्पोज़ करके ओपीनियन पोल करवाया जाए ।

पी० डी० एक्ट के तहत जितने डेटेन्यूज़ आपने नज़रबन्द कर रखे हैं उनको आप फ़ौरी छोड़िये, उनको आप रिहा कीजिये । पी० डी० एक्ट आप उन पर लागू न करें । उसकी आड़ में वहां गवर्नमेंट जुल्म कर रही है । इसकी आड़ ले कर तमाम तेलंगाना के लीडर्ज़ को नज़रबन्द वहां कर दिया गया है । जितने भी इस एक्ट के तहत लोग नज़रबन्द किये गए हैं उन सब को राज मुंदरी जेल में रखा गया है । इनको आप वहां न रखें । हम लोगों ने इसके बारे में रिप्रिजेंट भी किया है कि उन लोगों को किसी और जगह आप मुंतकिल करिये । जो उनको वहां मैंटल एगोनी होती है, उससे उनको आप बचाइये । लेकिन आप इस चीज़ को भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं । मुझे शक है कि ये लोग बातचीत भी नहीं करेंगे । सिर्फ एकसालमियत और यकजहती के नाम पर तेलंगाना को लूटना चाहते हैं । सरकार को क्या एतराज़ है कि डेटेन्यूज़ को रिहा करके राउंड टेबल कान्फ्रेंस करे ? एक पार्लिमैंटरी डैलीगेशन भेजने में क्या एतराज़ है । तेलंगाना सरप्लस के बारे में कई बातें कही गई हैं । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एक सरकारी इदारा है इंस्टीट्यूट आफ इकोनोमिक ग्रोथ । यह दिल्ली में है । उसने सरप्लस वर्क आउट किया है । उसने बताया है कि एक सौ करोड़ से ज्यादा रुपया तेलंगाना का आंध्र में खर्च किया है । इसको भी आप देख सकते हैं । चौदह तारीख को असैम्बली की मीटिंग हुई थी । उस में गवर्नर अपना एड्रेस पढ़ भी नहीं पाए । पहले हमने इस बात को बंगाल में सुना था और दूसरी बार आंध्र प्रदेश में सुना है । यह अच्छी चीज़ नहीं है । वहां तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है । उस में 202 कांग्रेस के मेम्बर हैं । आप यह भी देखें कि असैम्बली मीट होने से कुछ समय पहले तीन एम० एल० ए० और एम० एल० सी० को गिरफ्तार कर लिया गया । वेकवर्धनी स्कूल में जो लाठीचार्ज हुआ और उस में जो लोग जख्मी हुए उन में एक एम० एल० ए० भी थे । क्या यह सब जलियांवाला बाग कांड से कुछ कम है । शर्म आनी चाहिए हमारी हकूमत को इन सब बातों पर । अगर वक्त पर एकशन नहीं लिया गया, वक्त पर काम नहीं किया गया तो वहां सिविल वार हो जायेगी, यह मैं आपको वार्निंग देता हूं ।

आखिर में एक शेर पढ़ कर मैं खत्म करता हूं :

जो हक की खातिर जीते हैं
मरने से कहां डरते हैं जिगर ।
जब वक्त शहादत आता है
दिल सीनों में रकस करते हैं ।

[شری گنٹا ریڈی (عادل آباد) : جناب صدر محترم، میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع عنایت کیا - یہ مسئلہ 1½ کروڑ تلنگانہ میں رہنے والے انسانوں کا ہے - آٹھ مہینے سے یہاں عام زندگی معطل ہوچکی ہے، پورے مدرسے بند ہیں، اور سولہ لاکھ بچے ایک سال گنوا چکے ہیں اور دوسرے سال کے دو مہینے گنوا چکے ہیں اور اس پرابلم کا کوئی حل ابھی نظر نہیں آتا - جہاں تک دو سو سے اوپر لوگ گولی کا نشانہ بنے، پچاس ہزار کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور بہتوں کو پی - ڈی - ایکٹ میں گرفتار کیا گیا اور راجمندھری جیل میں رکھا گیا لیڈروں کو - آج ہر بچے کی زبان پر

نہیں یہ اس سے پتہ چلے گا کہ ہر معاملے میں ملازمت، اُجرت، اور ترقی کے معاملے میں ناانصافی کی گئی ہے - جہاں تک کہ تلنگانہ ریجنل کونسل کو کمیٹی میں تبدیل کردیا گیا - اور یہاں تک کہ آرگنا ئزیشن لیول میں تلنگانہ پردیش کمیٹی کو 1962 تک برقرار رکھنے کے بجائے آندھرا پردیش میں ضم کر دیا گیا - شروع سے ہی ڈپٹی چیف منسٹر کا عہدہ برخاست کر دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اُنہوں نے فاتحانہ طریقے پر کام کیا ہے اور تیرہ سال تک تلنگانہ والے اس کو برداشت کرتے رہے—میں کہونگا کہ تلنگانہ والے کمزور نہیں ہیں - بلکہ وہ شریف ہیں - اُن کی شرافت کا بےجا فائدہ اُٹھانا چاہتے ہیں - تلنگانہ والے حق کے لئے لڑ رہے ہیں - بھگوت گیتا میں کہا گیا ہے کہ حق کے لئے لڑنا دھرم ہے - اگر حق کے لئے نہ لڑا جائے تو بزدلی ہے -

پولیس کی زیادتیوں کا ذکر دوسروں نے کیا ہے کہ بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑیوں میں بغیر وردیں کے جا کر کیا کیا ظلم کرتے ہیں - کہا جاتا ہے کہ غنڈے بھی پولیس کے دل میں شریک ہو کر لوٹ مار کرتے ہیں - اکثر لوگوں نے کہا کہ تلنگانہ والوں نے آندھرا والوں پر بہت ظلم کئے - مگر کسی اخبار میں یہ نہیں آیا کہ کسی کو مارا گیا کسی کی عصمت لوٹی گئی - اگر ایسا ہے تو میری ایک مانگ ہے کہ ہوم منسٹر صاحب ایک کمیٹی مقرر کریں اور جانچ کرائیں کہ کتنوں کے ساتھ ظلم یا زبردستی کی گئی تاکہ جو غلط قسم کی افواہیں ہیں جلدی دور ہوں -

مشہرآباد جیل میں ملزموں نے

[شری گنگا ریڈی]

یہ ہے کہ تلنگانہ الگ بنے - کیا ان کی یہ قربانی بےکار جائیگی، کیا انسان کا خون پانی سے سستا ہو گیا ہے ؟ میں یقین کے ساتھ کہوں گا کہ یہ قربانی بےکار نہیں جائیگی، خون اپنا رنگ ضرور لائیگا -

تلنگانہ میں جو ظلم زیادتی ہوئی ہے اُس کا کہنا مشکل ہے - اُن ماؤں سے پوچھئے جن کے بچے مارے گئے - اُس بیوی سے پوچھئے جس کی مانگ کا سیندھور مٹا - اُس باپ سے پوچھئے جس کی آنکھوں کا نور اور بڑھاپے کا سہارا چھوٹا - اُن یتیم بچوں سے پوچھئے جن کے باپ مارے گئے - جب اتنا بھیانک معاملہ نظروں سے گزرتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں - ہمارے دھرم میں کہا گیا ہے کہ باپ کے کئے ہوئے پاپ کا پھل بچوں کو بھگتنا پڑتا ہے، حکومت کی کی ہوئی غلطی کی سزا عوام کو بھگتنی پڑتی ہے - یہی وجہ ہے کہ ریاست آندھرا پردیش جو ایک سرسبز اور شاداب رہی ہے، مسلسل سوکھے اور باڑھ کا شکار بنی ہوئی ہے -

فضل علی کمیشن نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ حیدرآباد کو الگ سٹیٹ رکھا جائے - مگر دونوں پنڈتوں نے، پنڈت نہرو اور پنڈت پنت نے تلنگانہ اور آندھرا کی خلاف مرضی کے دونوں کی شادی کرا دی - نتیجہ یہ ہوا کہ طلاق کی نوبت پیدا ہو گئی ہے میں آپ سے کہونگا کہ ایک جینٹلمین ایگریمنٹ بنایا گیا تھا، اُس کا اگر صحیح طریقے سے اُردو میں ترجمہ کروں تو شریفوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے - تو دو شریف ہیں یا

کس بےرحمی سے ستہ گرھیوں کو پیٹا - وہ اخبار میں شائع ہوا تھام اور جیلوں میں پولیس کا جو لاتھی چارج ہوا اس سے بھی سب واقف ھیں - ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھنا چاھتا ھوں - تلنگانہ کے کسی جیل میں جگہ نہیں ھے - مدرسوں کو جیلوں میں تبدیل کر دیا گیا - میرے ضلع میں انڈسٹریل سٹیٹوں کوم جو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھیں، جیل خانہ بنادیا گیا - آج لا اینڈ آرڈر باقی نہیں ھے - وھاں کے نمائیندوں کا عوام سے کیا تعلق ھے یہ آپ خود جانتے ھیں - اگر ھمارے دستور میں رکال کا پرووپزن ھوتام آج ھم یہاں نہیں ھوتے - آج ھم لوگوں کی کوئی وقعت ھماری کانسٹی‌ٹیونسی میں نہیں ھے - پورے عوام اس عوامی تحریک میں حصہ لے رھے ھیں اور ھم اُن سے کٹ چکے ھیں - این - جی - اوج کی پینتیس روزہ ھڑتال وھاں چلی - پینتیس روز تک دفتر بند رھے - دفتر تو بند نہیں رھے لیکن وھاں کاروبار نہیں ھوا - اگر پیٹ کی مجبوری نہ ھوتی تو میں یقین کے ساتھ کہتا ھوں کہ دفتر کبھی نہ چلتے - کیونکہ پیٹ کی مجبوری تھی، بیوی بچوں کی آھیں وہ دیکھ نہیں سکے لحاظہ مجبوراً ھڑتال بند کر دفتر جانا پڑا - وھاں پر آٹھ مہینے سے پراھبیٹری آرڈر ھے - کچھ دن تک وھاں کمپلیٹ کرفیو رھا - اس سے حیدرآباد اور سکندرآباد میں بیوگی کا عالم تھا -

میں کہونگا کہ سنیٹرل گورنمنٹ نے ایک آٹھ نقاطی پروگرام بنایا جو بالکل غیرتسلی بخش اور ناکام ثابت ھوا - وھاں جون میں غیر دانشمندانا طریقہ پر پولیس کے زور پر مدرسے کھول کر کورس کمپلیٹ نہ ھونے کے باوجود امتحان منعقد کرنا چاھام جس کا نتیجہ کیا ھوا ؟ بدامنی پھیلی - بچوں پر فائرنگ کی گئی جس سے پچاس بچے مرے - اس سے وھاں کی حالت صاف ظاھر ھوتی ھے -

آندھرا پردیش میں پورے الکشن ملتوی ھوگئے ھیں - پنچائت الکشن بھی ملتوی کر دے گئے - حیدرآباد میونسپل کمیٹی کے الکشن ملتوی کر دیئے گئے - کیا وجہ ھے ؟ اگر الکشن منعقد ھوتے تو ایک بھی کانگریس کا ممبر چن کر نہیں آسکتا تھا - ابھی حال ھی میں میں نے اخبار میں پڑھا کہ حیدرآباد سب کمیٹی کے الکشن ھوئے جس میں سپیٹ پرسینٹ تلنگانہ نعرہ لگانے والوں نے پوری سیٹیں کیپچر کر لیں - اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ھیں کہ یہ کتنا عوامی مووومینٹ ھے - حیدرآباد میں ایم - ایل سیز کا الکشن ھوا - اُس میں پرجا سمتی کے سیکریٹری وینکٹراما ریڈی چن کر آئے - حالانکہ پیسے کی طاقت پر سرکاری کینڈیڈیٹ کو بیک کیا گیا پھر بھی وینکٹراما چن کر آئے - یہ خود ثبوت ھے کہ تلنگانہ کا اندولن کس حد تک مضبوط ھوچکا ھے -

بدامنی کی حالت یہ ھے کہ جو وزرا استیفہ دے چکے ھیں انھوں نے ایک زبان ھو کر مانگ کی تھی کہ یہاں پر پریذیڈنیٹ راج امپوز کیا جائے کیونکہ یہاں پر امن و امان برقرار نہیں ھے - پرائم منسٹر کا ایوڈیشم راتوں رات آکر واپس چلے جانا اور اُس کے بعد شری چوان کی آمد ، تین دن تک گفتگو ، اس سب سے یقین آیا تھا کہ یہ مسئلہ حل ھوگا اور یہ لوگ دلچسپی لے رھے ھیں ، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا

[شری گنگا ریڈی]
پڑتا ہے کہ حالات جوں کے توں ہیں اور کچھ نہیں ہوا - ہوا کیا ؟ کابینہ کا توسیع یعنی ریاستی بےروزگار لیڈروں کے لئے کچھ ملازمتیں کھل گئیں اور سرکاری مالیت پر کچھ بھار پڑا لیکن اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے-

چونکہ یہ مسئلہ میرے علاقے کا ہے اس لئے میں کچھ سجیشن رکھنا چاہوں گا - اگر تلنگانہ نہیں بنا تو ہم اپنی کونسٹیچونیسی میں نہیں جاپائینگے-لا اینڈ آرڈر کی یہ حالت ہے- کہ آج بھی منسٹر وہاں کھلے عام نہیں پھر سکتے - اگر جائینگے تو پولیس کی بندوقوں اور برچھوں کے بل پر - آپ نے وزیر داخلہ کا کھم کا دورہ دیکھا ہوگا - ان کے دورے میں صرف چار جانیں گئیں - اگر ہر منسٹر کے دورے میں جانوں کے جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن آئے گا جب تلنگانہ کے لاکھوں لوگ گولیوں کے نشانے بن جائینگے -

اگر حکومت کو جمہوریت پر وشواس ہے تو رائے عامہ مقدم ہے اور ان کو رائے عامہ کو سننا پڑے گا - آج سینٹر نے کیا کیا ؟ ہم نے مانگا پارلیمینٹری ڈیلیگیشن، انہوں نے کہا نہیں ہم نے کہا سب کمیٹی دیجئے، انہوں نے کہا نہیں جیسا گجیندر گڈکر کمیٹی نے کہا، اس کو موقعہ دیا جائے، تلنگانہ کی ریجنل کمیٹی کے اختیاروں میں اضافہ کیا جائے ، تو کہا نہیں - میں کہنا چاہونگا کہ اب وقت آگیا ہے کہ ہم اس پر از سرے نو غور کریں - جیسا میرے دوست نے کہا کہ ہم آئیڈیو لوجی کی خاطر ہزاوں لوگوں کی جانیں نہیں لے سکتے، آئیڈیولوجی کی خاطر کروڑوں آدمیوں کو قربان نہیں کرسکتے - وقت آگیا ہے کہ ہم از سرے نو اس پر سوچیں کہ تنظیم جدید کس طرح کی جائے - اس کے لئے ایک ایس - آر - سی - کمیٹی بٹھائیۓ اور اس کی جو ریکمنڈیشن آئے ہم اس پر سوچیں کہ اس کے بارے میں کیا ترمیمات کی جائیں اگر اکسالمیت کو اُس سے نقصان پہنچتا ہے، اگر چھوٹی ریاستیں بننے سے ملک کی اکسالمیت کو خطرہ پیدا ہوتا ہے تو میں پونچھونگا کہ ہریانہ اور ناگالینڈ بنا تھا تو یہ نعرہ کدھر گیا تھا - اُس وقت سالمیت کی بات نہیں کہی گئی - جب جب موافق کوئی چیز بیٹھی ہے - اس وقت تو وہ ٹھیک ہوتی ہے لیکن جب کوئی چیز سوٹ نہیں کرتی ہے تو آپ یک لمیت اور دوسری اس طرح کی چیز بیچ میں لاتے ہیں-میں کہونگا کہ اگر چھوٹے راجیہ بنیں گے سینٹر مضبوط ہوگا - سنٹر کو مضبوط ہونا بھی چاہئے - جو حالات اس وقت چل رہے ہیں ان میں مظبوط سینٹر کی ضرورت ہے - تیلنگانہ آپ نے دیا تو سینٹر کمزور نہیں ہوگا بلکہ مضبوط ہوگا -

میں کہتا ہوں کہ آپ اوپنین پول وہاں کرائے - اگر اوپنین پول کرانا ہے تو جو وہاں اس وقت حکومت ہے اس کا بہت زیادہ اثر پڑیگا اس لئے وہاں پول کروائیں - آپ تین مہینے کے لئے پریزیڈنٹل رول امپوز کرائے اور اس بیچ میں اوپنین پول کروائیں - آپ لوگوں کی رائے جانئے اور یہ تب ہی جانی جاسکتی ہے جب وہاں پریزیڈنٹل رول امپوز کر کے اوپنین پول کروایا جائے -

پی - ٹی - ایکٹ کے تحت چلنے ڈیٹینیوز آپ نے نظر بند کر رکھے ہیں

ان کو آپ فوری چھوڑئیے، ان کو آپ رہا کیجئے—پی - ڈی - ایکٹ آپ ان پر لاگو نہ کریں - اس کی آڑ میں وہاں گورنمنٹ ظلم کر رہی ہے - اس کی آڑ لے کر تمام تیلنگانہ کے لیڈرز کو نظر بند وہاں کر دیا گیا ہے - جتنے بھی ایکٹ کے تحت لوگ نظر بند کئے گئے ہیں ان سب کو راجمندری جیل میں رکھا گیا ہے - ان کو آپ وہاں نہ رکھیں - ہم لوگوں نے اس بارے میں ریپریزنیٹ بھی کیا ہے کہ ان لوگوں کو کسی اور جگہ آپ منتقل کرئیے - جو ان کو وہاں مینٹل اگونی ہوتی ہے، اس سے ان کو آپ بچائیے - لیکن آپ اس چیز کو بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں - مجھے شک ہے کہ یہ لوگ بات چیت بھی نہیں کرینگے - صرف یکسالمیت اور یکجہتی کے نام پر تیلنگانہ کو لوٹنا چاہتے ہیں - سرکار کو کیا اعتراض ہے کہ ڈیٹینیوز کو رہا کر کے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کرے - ایک پارلیمنٹری ڈیلیگیشن بھیجنے میں کیا اعتراض ہے -

تلنگانہ سرپلس کے بارے میں کئی باتیں کہی گئی ہیں - میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ایک سرکاری ادارہ ہے، انسٹی ٹیوٹ آف اکانامک گروتھ یہ دہلی میں ہے - اُس نے سرپلس ورک آوٹ کیا ہے - اُس نے بتایا ہے کہ ایک سو کروڑ سے زیادہ روپیہ تلنگانہ کا آندھرا میں خرچ کیا ہے - اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں - 14 تاریخ کو اسمبلی کی میٹنگ ہوئی تھی - اُس میں گورنر اپنا ایڈریس پڑھ بھی نہیں پائے - پہلے ہم نے اس بات کو بنگال میں سنا تھا اور دوسری بار آندھرا پردیش میں سنا ہے - یہ اچھی چیز نہیں ہے - وہاں تو کانگریس کی گورنمنٹ ہے - اس میں 202 کانگریس کے ممبر ہیں - آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسمبلی میٹ ہونے سے کچھ سمے پہلے تین ایم ایلیز - اور ایم ایل سی - کو گرفتار کر لیا گیا - ویکور دھنی سکول میں جو لاٹھی چارج ہوا اور اس میں جو لوگ زخمی ہوئے اُن میں ایک ایم - ایل - اے - بھی تھے - کیا یہ سب جلیانوالا باغ سے کچھ کم ہے ؟ — شرم آنی چاہئے ہماری حکومت کو ان سب باتوں پر—اگر وقت پر ایکشن نہیں لیا گیا، وقت پر کام نہیں کیا گیا تو وہاں سول وار ہو جائیگی، یہ میں آپ کو وارننگ دیتا ہوں - آخر میں ایک شعر پڑھ کر میں ختم کرتا ہوں -

جو حق کی خاطر جیتے ہیں، مرنے سے
کہاں ڈرتے ہیں جگر
جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں
میں رقص کرتے ہیں -]

MR. SPEAKER: This debate will continue on 21st August. Shri M.N. Reddy and Shri Prakashvir Shastri will be given a chance after other members from parties have spoken :

18.03 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, August 19, 1969/Sravana 28, 1891 (Saka).